

न्यूज़ ब्रीफ



भारत दौर पर आ रही जापानी पीएम सानाए ताकाइची; पीएम मोदी के साथ 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में महामंथन

नई दिल्ली, एजेंसी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगी। इस दौरान नई दिल्ली में 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें दोनों देशों के शीर्ष नेता द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे।

यह प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। यह दौरा अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा और वहाँ आयोजित 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद हो रहा है। इसे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और जापान के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, डिजिटल सहयोग, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, समीकंडक्टर, आधुनिक श्रृंखला और लोगों के बीच संपर्क जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भविष्य के सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

महबूबा मुफ्ती का बड़ा आरोप, 'पैसे लेकर नौकरी बाँट रही उमर अब्दुल्ला सरकार, पिछले दरवाजे से दी गई 25 हजार नौकरियाँ'



जम्मू एजेंसी | जम्मू कश्मीर में विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने उमर अब्दुल्ला सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉंग्रेस (नेका) सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेश में पिछले दरवाजे से 25,000 लोगों की भर्ती की है। महबूबा ने संवाददाताओं से कहा, "नेका सरकार के 25 महीनों के कार्यकाल में लगभग 25,000 लोगों की भर्ती पिछले दरवाजे से की गई। मेरे पास इनके आदेश हैं लेकिन मैं उनकी पहचान उजागर नहीं करना चाहती, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे।" उन्होंने कहा, "ये सामान्य पद नहीं थे बल्कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पद थे, जिन्हें सरकार ने अपने चर्चियों, विधायकों और गठबंधन सहयोगियों को दे दिया। मुझे लगता है कि इसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी है, इसलिए वे चुप हैं और इस मुद्दे पर कोई हो-हल्ला नहीं कर रहे हैं।"

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी को इन नियुक्तियों को लेकर शिकायतें मिली थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उम्मीदवारों से दो से तीन लाख रुपये लिए। महबूबा ने दावा किया, "इसके लिए लगभग 200 निजी 'आउटसोर्सिंग एजेंसियों' का इस्तेमाल किया गया। कुछ समय के लिए एक वेबसाइट खुली रही, जहाँ उम्मीदवारों से आवेदन करने को कहा गया। जैसे ही वे आवेदन जमा करते थे, वेबसाइट बंद हो जाती थी।"

सशक्त लोकतंत्र ही हमारी पहचान, हम लोकतंत्र सेनानियों का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

• भोपाल प्रतिनिधि
भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र हित में ही सबका हित निहित है। सशक्त लोकतंत्र ही भारत राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने देश को वैश्विक पटल पर एक विशिष्ट और सम्मानजनक पहचान दिलाई है। लोकतंत्र सेनानियों ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए अपना खून-पसीना बहाया, अमानवीय अत्याचार सहे और अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा हम सभी भारतवासी इन लोकतंत्र सेनानियों का ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। आज देश की एकता, विविधता, अखंडता और अक्षुण्णता इन्हीं साहसी, समर्पित एवं राष्ट्रनिष्ठ कर्मवीरों की ही देन है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रवीन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों



के प्रादेशिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कठिन से कठिन यातनाएं सहने वाले वीर लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि उनका त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमूल्य स्रोत है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जायवा, जिला रतलाम निवासी 96 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी श्री लक्ष्मी नारायण पाटीदार और 95 वर्षीय लोकतंत्र सेनानी श्री शांतिलाल संघवी सहित आपातकाल के दौरान प्रमुख भूमिका में रहे पूर्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता का शोल्ड

प्रदान कर अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रादेशिक सम्मेलन में आए सभी लोकतंत्र सेनानियों पर पुष्प-वर्षा कर उनका स्वागत-सम्मान किया। सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम् गायन के साथ हुआ। सम्मेलन में देश में आपातकाल पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आपातकाल पर केंद्रित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

पर शिलालेख लिखवाये जायेंगे एवं उनके गांव, कस्बे, नगर या निवास क्षेत्र के समीप मौजूद सार्वजनिक भवनों, पार्क एवं रोड आदि का नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्चा अब सरकार उठाएगी। किसी लोकतंत्र सेनानी के बीमार पड़ने पर उन्हें उच्चतम और बड़े स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए पीएमश्री एयर एंबुलेंस की निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र दिया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों द्वारा अपने निवास के पते पर बदलाव होने पर उन्हें दी जा रही सम्मान निधि से संबंधित बैंक या शाखा बदलने की सुविधा भी दी जाएगी। किसी भी शासकीय कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों के पहुंचने पर संबंधित अधिकारी पूरे सम्मान और प्राथमिकता के साथ इनकी बात सुनेंगे तथा इनके सुझाव भी माने जाएंगे।

लोकतंत्र सेनानियों के हित में की घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में लोकतंत्र सेनानियों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर उन्हें तीर्थ दर्शन कराया जायेगा। इनके लिए शासकीय रेस्ट हाउस में 2 दिन तक रूकने की व्यवस्था भी की जाएगी। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों के नाम

ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान, पहली बार सामने आए नाम, नेशनल वॉर मेमोरियल में मिली जगह

• नई दिल्ली, एजेंसी
नई दिल्ली | 22 अप्रैल 2025 को पहलवान में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया



वीर चक्र और साजेंट सुरेंद्र कुमार को मरणोपरान्त वायु पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले वीर सैनिकों में सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अनिलवीर मूड मुरली नाटक, हवलदार सुनील कुमार सिंह और भारतीय वायुसेना के साजेंट सुरेंद्र कुमार शामिल हैं।

आप और पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन में सेना के 6 वीर जवानों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। अब इन शहीदों के नाम नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर दर्ज किए जाएंगे।

सार्वजनिक किए गए शहीदों के नाम - ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इन सभी शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। शहीदों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं। शहीदों के नाम नई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए जा रहे हैं, जिससे उनका बलिदान सदैव राष्ट्र की स्मृतियों में जीवित रहेगा। इन छह शहीदों में से दो को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया है। इनमें राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरान्त

राम मंदिर मामला: कड़ियों की ड्यूटी के बाद नहीं होती थी तलाशी, सिफारिश पर मिला था नोट गिनने का काम

• नई दिल्ली, एजेंसी
नई दिल्ली, एजेंसी | राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार (26 जून) को अदालत में पेश किया। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कोर्ट की बताया कि शुरुआती जांच में सभी के खिलाफ चोरी के सबूत मिले हैं। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी चढ़ावे के पैसे और जेवर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।



चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी : रामशंकर यादव उर्फ टिट्ठू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्लाए करुणेश पांडेयए लवकुश मिश्रए रामशंकर मिश्रए सुभाष श्रीवास्तव मनीष कुमार यादव

और रमा शंकर मिश्र गिनती के बाद अपने साथ कैश और ज्वेलरी जेब में रखकर बाहर ले जाते थे। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि 7 आरोपियों के पास से अब तक करीब 79.84 लाख रुपये बरामद किए जा चुके हैं। ये रिकवरी 7 आरोपियों की निशानदेही पर हुई है। 8वें आरोपी सुभाष श्रीवास्तव के पास से रिकवरी नहीं हुई है, वो साजिश का हिस्सा है।

गहरी खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, मां-बेटे सहित छह लोगों की मौत



शिमला, एजेंसी | हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में मां-बेटे समेत छह लोगों की मौत हो गई है। पुलिस थाना रामपुर के तहत आने वाले दुर्गम क्षेत्र काशापाट जा रही एक पिकअप गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 200 फीट नीचे तकलेच-देवटी सड़क किनारे जा गिरी। सूचना मिलने के बाद पुलिस का दल मौके के लिए रवाना हुआ। ग्रामीणों की मदद से राहत कार्यों को अंजाम दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

नकली संविधान बचाने वाले राहुल 'गायब'! बीजेपी का तंज, कहा- अब कांग्रेस को कौन बचाएगा?

• नई दिल्ली, एजेंसी
नई दिल्ली | भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गैर-मौजूदगी पर खाली उठाते हुए कहा है कि वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस ने अभी तक इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीजेपी ने X पर एक पोस्ट में कहा, "जैसे ही देश में चुनाव आते हैं... हार के बाद विदेश चले जाना, यही राहुल गांधी की असली पहचान है!" भाजपा ने पोस्ट में चुनाव जीतने या हारने का नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों निभाने का भी है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने और



हरने तक ही सीमित है; देश की जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, लिखा कि देश की राजनीति में खाली सिर्फ बल्कि व्यवहार का भी हिसाब रखती है। पुरा देश बस एक ही सवाल पूछ रहा है: #राहुल_कहाँ_है?

बीजेपी ने एक ओर पोस्ट में लिखा कि Oh no! भारत के नकली संविधान बचाने वाले कहीं नहीं मिल रहे हैं! अब बेवस कांग्रेस को कौन बचाएगा? क्या हम कबूतरों के जरिए संदेश भेजें? दुध के कार्टन पर उनकी तस्वीर छापें? या फिर कोई नया रियलिटी शो शुरू करें: #WhereIsRahul? बीजेपी ने कई सार्वजनिक और संस्थागत मंचों पर गांधी की गैर-मौजूदगी पर अक्सर खाली उठाए हैं और इसे संसदीय कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी और संवैधानिक परंपराओं का अनादर बताया है

मुहूर्म पर विवाद! दरभंगा में एसआई को मारी गोली, गुस्साई भीड़ ने हमलावर को मार डाला

• नई दिल्ली, एजेंसी
नई दिल्ली | बिहार के दरभंगा में शुक्रवार (26 जून, 2026) की सुबह दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। पूरा मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के उझील गांव का है। शुक्रवार तड़के मुहूर्म के दौरान अखाड़े की ट्यूब लाइट बुझाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया।



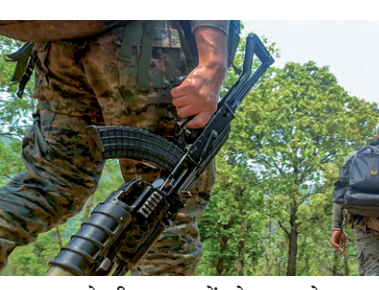
जानकारी के अनुसार, ट्यूब लाइट बुझाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई झड़प के दौरान उझील गांव निवासी दिलीप सहनी के पुत्र सुनील सहनी (उम्र 30-31 साल) ने मो.

मुहूर्म की छुट्टी में घर आए थे. वो पटना जिला बल में सहायक अंतरिरीक्षक (एसआई) के पद पर कार्यरत हैं. गोली चलने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसी दौरान मौजूद लोगों ने सुनील को घेर लिया और मारपीट शुरू हो गई. मारपीट के दौरान किसी ने धारदार फरसा से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

बस्तर में नक्सलियों पर डबल स्ट्राइक, भारी हथियार और 24 लाख नकद बरामद

• रायपुर, एजेंसी

रायपुर | पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के जंगलों में छिपे माओवादियों के दो ठिकानों से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री और 24 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च को छत्तीसगढ़ को हथियारबंद नक्सलवाद से मुक्त घोषित किए जाने के बाद बस्तर क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। टोपें माओवादियों द्वारा पहले छिपाए गए नकदी, हथियारों और विस्फोटकों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बस्तर में सात जिले शामिल हैं, जिनमें नारायणपुर भी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि खास खुफिया जानकारी के आधार



पर, इस हफ्ते की शुरुआत में ओरछा और छोटेडोंगर पुलिस थाना क्षेत्रों में अलग-अलग तलाशी अभियान चलाए गए। ओरछा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकला के जंगली पहाड़ी इलाकों में चलाए गए अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों को जंगल में छिपाकर रखा गया माओवादियों का एक डंप मिला, जिसमें हथियार, गोला-बारूद, संचार उपकरण और अन्य सामान मौजूद थे। अधिकारी

ने बताया कि बरामद हथियारों और गोला-बारूद में एक INSAS राइफल, दो INSAS मैगजीन और 21 राउंड, दो SLR राइफल, चार SLR मैगजीन और 63 जिंदा राउंड, दो .303 राइफल, दो .303 मैगजीन और 65 जिंदा राउंड, दो 30-OC बंदूकें, नौ मैगजीन और 36 जिंदा राउंड, एक BGL लॉन्चर, एक सिंगल-शॉट बंदूक, तीन डेटोनेटर, दो स्केनर और 6.7 mm के 28 राउंड शामिल थे।

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया न्याय का भरोसा, उज्वल निकम बनेंगे स्पेशल प्रॉसिक््यूटर

• रायपुर, एजेंसी

मुंबई | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे में पीडित के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाकात के बाद लोहगढ़ किले में हुई हत्या के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया और सीनियर वकील उज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक््यूटर नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि फडणवीस ने परिवार की मांगें तुरंत मान लीं और कानून और न्याय विभाग के सचिव को निर्देश जारी किए। निकम ने इस मामले में स्पेशल प्रॉसिक््यूटर के तौर पर पेश होने के लिए अपनी सहमति दे दी है। केतन अग्रवाल के पिता, विशाल अग्रवाल ने पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की। महाराष्ट्र CMO ने बताया कि हम यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध हैं



कि इस मामले में दोषियों को सबसे कड़ी सजा मिले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और उज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक््यूटर नियुक्त करने की उनकी मांग को भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मान लिया और कानून और न्याय विभाग के सचिव को इस बारे में निर्देश जारी किए। सीनियर वकील उज्वल निकम ने

भी इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक््यूटर के तौर पर काम करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। फडणवीस ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया और कहा कि इसने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पढ़े-लिखे और अच्छे-खासे परिवारों के बच्चों में 'बुरी और विनाशकारी सोच' क्यों पनपती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मामले को सिर्फ एक अपराध के तौर पर न देखें, बल्कि इसे सामाजिक नजिए से भी देखें।

बीजिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग से टकराया विमान

• नई दिल्ली, एजेंसी

चीन की राजधानी बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत सीआईटीआईसी टावर' से शुक्रवार (26 जून 2026) को अचानक एक विमान टकरा गया। इस हादसे में गगनचुंबी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और विमान का मलबा नीचे जमीन पर आ गिरा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजिंग के गुओमाओ जिले की इस 109 मीटर इमारत को चाइना जून भी कहा जाता है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान टावर के एक हिस्से से टकराया, जिससे इमारत की करीब दो खिड़कियां टूट गईं और टक्कर लगते ही विमान के टुकड़े-टुकड़े हो गए। विमान का हिस्सा ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि जमीन पर फैले मलबे से धुआं उठता नजर आ रहा है। इस हादसे के बाद तुरंत पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग के आसपास भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। वहां से गुजरने वाले लोगों को इमारत की तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक रही है। राहत बचाव कार्य को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने बिल्डिंग के आसपास की कई सड़कों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है।

प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मकरोनिया में देखा अमृत 2.0 का काम; 2 एकड़ जोन में 1,000 पौधों के रोपण के साथ वृहद पर्यावरण अभियान शुरु

भू-जल स्तर बनाए रखना और जल संरचनाओं का संरक्षण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी --- उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रभारी मंत्री ने रोपा नारियल का पौधा

सागर, प्रतिनिधि

सागर | मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में आज मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। उन्होंने यह नारियल का पौधा रोपकर वृहद पौधारोपण की शुरुआत की। नरयावली विधायक प्रदीप लारिया के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अमृत 2.0 योजना के कार्यों का मूल्यांकन करने के साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 'एक पेड़ मां के नाम' वृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सांसद श्रीमती लता वानखेड़े, जिला अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा

पाल, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और जन समुदाय विशेष रूप से उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने मकरोनिया क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास की सराहना की। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'अमृत योजना' को स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने बखूबी धरातल पर उतारा है। क्षेत्र के निरंतर 4 बार के विधायक ने जनता के दिलों में स्थान बनाकर विकास को प्राथमिकता दी है। पुराने कुओं, बावडियों और पारंपरिक जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल को सहेजकर जमीन के भीतर पहुंचाना और वाटर टेबल (भूजल स्तर) को बनाए रखना हम सभी की सामाजिक जिम्मेदारी



है। वर्षा के जल का संचय करना और उसे वापस भूमि में पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी के प्रति यह हमारी जिम्मेदारी भी है। सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने मकरोनिया क्षेत्र में तेज गति से हो रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने यहां बन रहे भव्य रविदास मंदिर निर्माण, शबरी जलाशय के सुदरीकरण और क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के सुदरीकरण हेतु स्थानीय विधायक,

प्रशासनिक और जनभागीदारी के प्रयासों की सराहना की। विधायक श्री प्रदीप लारिया ने क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी दी और कहा कि क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से विकास हो रहा है। आज यहां करीब 1.60 करोड़ की लागत से शबरी जलाशय/सरोवर का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही 72 लाख की लागत से 'शबरी पार्क' का निर्माण भी जारी है, जिसे एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान अभियान के तहत यहां करीब 2 एकड़ क्षेत्र को विशेष वन जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ कुल 1,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य है। विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण एवं अनुकंपा नियुक्ति अमृत 2.0 योजना

के अंतर्गत निर्माणाधीन पार्क और वॉटर बॉडी विकास कार्यों का निरीक्षण करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और उच्च गुणवत्ता के साथ समय-समीमा में पूरे किए जाएं। हितग्राहियों को राहत-प्रशासनिक संवेदनशीलता के अंतर्गत कार्यक्रम के दौरान दो पात्र हितग्राहियों—श्री आशु जाटव एवं श्री प्रिंस दुबे—को मुख्य अतिथियों द्वारा शासकीय सेवा हेतु अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष, क्षेत्र के पार्षदगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, कार्यवाही संस्थाओं के इंजीनियर्स एवं मकरोनिया क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सागर में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा : उप मुख्यमंत्री ने दिए विधानसभावार मॉनिटरिंग के निर्देश, पौधे बचाने वाली संस्थाएं होंगी पुरस्कृत

» हमारा लक्ष्य केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करना है
उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल

सागर, प्रतिनिधि

सागर | मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' की जिला स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा जल के अधिकतम संचयन हेतु फार्म पॉन्ड्स के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण, पर्यावरण-अनुकूल और लोकहितकारी कार्य सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी कार्यों की विधानसभावार मॉनिटरिंग करने और शेष बचे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

पौधों के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन निकायों, संस्थाओं आदि द्वारा लगाए



गए पौधे अगले वर्ष तक सर्वाधिक संख्या में जीवित और सुरक्षित रहेंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाए जिससे संबंधितों को प्रोत्साहन मिले। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा लक्ष्य केवल पौधारोपण नहीं, बल्कि पौधों के वृक्ष बनने तक उनकी सुरक्षा करना है। खुरदरे विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने अगवत काय्या कि खुरदरे में इस वर्ष एक दिन में 1 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों की सहभागिता रहती है।

गत वर्ष भी वृहद पैमाने पर यह गतिविधि की गई थी जिसमें पौधारोपण करने वाले सभी व्यक्ति नियमित रूप से उनके द्वारा लगाए गए पौधों की फोटो अपलोड करते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उस पौधे को सही देखभाल मिल रही है। पौधों की एक गर्जिन की तरह सेवा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन ने शहरी क्षेत्र में रेनवाटर

हावेंस्टिंग को सक्रिय करने और लाखों बंजारा झील पर गंगा आरती के माध्यम से आई जन-जागरूकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सागर नगर में भी उचित स्थान को देखते हुए करीब 25 हजार पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है। देवरी विधायक श्री वृजबिहारी पटेल, बंडा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी ने भी उनके क्षेत्र ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी दी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत ने जहां बाउंड्री नहीं है वहां रोपे गए पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री-गार्ड उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अभियान के तहत विगत दो वर्षों में किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग और गैप फिलिंग करने साथ ही अभियान के तहत आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही। जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का प्रेजेंटेशन देते हुए जिला

पंचायत सीईओ श्री विवेक केजी ने बताया कि सागर जिला जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर चुका है और लगातार इसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सांसद श्रीमती लता वानखेड़े, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री भूपेंद्र सिंह, सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन, देवरी विधायक श्री वृजबिहारी पटेल, बंडा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी, महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरासिंह राजपूत, अध्यक्ष नगर निगम श्री वृंदावन अहिरवार, जिला अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी, श्रीमती रानी कुशवाहा, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ श्री विवेक केजी, डीएफओ श्री शैलेश माचरा एवं श्री वरुण यादव, नगर निगम कमिश्नर श्री राजकुमार खत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

तिरंगे का अपमान करने वालों पर कार्रवाई, तीन बुंदेली रीलबाजों पर एफआईआर दर्ज की गई



सागर, प्रतिनिधि

सागर | सागर में सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने वाले तीन बुंदेली क्रैटोरों के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इन युवाओं द्वारा बनाए गए एक वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चोर अपमान किया गया है, साथ ही वीडियो के बैकग्राउंड में अश्लील गाना भी बजाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स में भारी आक्रोश देखा जा रहा था।

रील के चक्कर में फंसे

बुंदेली कलाकार

जानकारी के मुताबिक, मामला सागर जिले का है जहां सोशल मीडिया पर बुंदेली भाषा और संस्कृति से जुड़ा कंटेंट बनाने वाले विशाल बांदरी, रानू रैक्वार और आदित्य ठाकुर कानूनी शिफ्ट में फंस गए हैं। तीनों ने मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सजग नागरिकों और संगठनों ने आपत्ति जताई। शिकायत में कहा गया कि मनोरंजन के नाम पर बनाए गए इस वीडियो में न सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, बल्कि पृष्ठभूमि

में बेहद आपत्तिजनक और अश्लील गाना भी इस्तेमाल किया गया।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू

मामले की संवेदनशीलता और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े होने के कारण सागर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत और गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला पंजीकृत कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो को कब्जे में लेकर उसके तकनीकी जांच की जा रही है।

दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सोशल मीडिया पर फूट लोगों का गुस्सा

वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर यूजर्स ने ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि व्यूज और लाइक्स पाने की होड़ में इस तरह की अश्लीलता और राष्ट्रध्वज का अनादर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है।

विधायक निर्मला सप्रे के मामले में कांग्रेस को झटका, हाईकोर्ट ने की उमंग सिंघार की याचिका खारिज



सागर, प्रतिनिधि

सागर | विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तरफ से दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रुसिया तथा जस्टिस प्रदीप मिश्र की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि विधानसभा स्पीकर कानून की प्रक्रिया का पालन हुए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के आवेदन की जांच कर रहे हैं। उनके द्वारा संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, इसलिए इस मामले में कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

बता दें कि सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने की मांग करते हुए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विधायक निर्मला सप्रे पार्टी विरोधी

गतिविधियों में लिप्त थीं। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई, 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं। कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है। दल बदल कानून के प्रकाश में उनका यह खेया गैर कानूनी है।

तथा था याचिका में?

याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के समक्ष बीना विधायक के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई 90 दिन के भीतर सुनिश्चित करना था। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दो साल से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी मामले की सुनवाई पूरी नहीं की गई। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गई है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन दिवस पर 196 गर्भवती महिलाओं एवं 65 बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

शिविर का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को विरोधन चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराते हुए सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना रहा।

सागर, प्रतिनिधि

निवाड़ी | कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल झामनानी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (PMSMA) दिवस का सफल आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर एवं निवाड़ी में किया गया। शिविर का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराते हुए सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना रहा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में यथार्थ सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, झंसी की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 83 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार किया गया।

परीक्षण के दौरान 25 हाई रिस्क गर्भवती माताओं की पहचान कर उनका समुचित प्रबंधन एवं फॉलोअप सुनिश्चित किया गया। 22 मॉडरेट एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाए गए। 3 महिलाओं को FCM (Ferric Carboxymaltose) इंजेक्शन प्रदान किए गए। 2 PIH (Pregnancy Induced Hypertension) के मामलों की पहचान कर उनका उपचार एवं आवश्यक प्रबंधन किया गया। विकासखंड निवाड़ी - विकासखंड निवाड़ी में डॉ. नेहा सक्सेना, डॉ. नेहा आर्य एवं डॉ. संगीता अग्रवाल द्वारा कुल 113 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया।

शिविर में 31 मॉडरेट एनीमिया से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाए गए। 4 महिलाओं को FCM इंजेक्शन प्रदान किए गए। सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन एवं कैल्शियम की दवाइयों का वितरण किया गया।

बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण - शिविर के दौरान



डॉ. सर्वेश पांडे द्वारा 65 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 13 बच्चे कुपोषित पाए गए, जिन्हें समुचित उपचार एवं पोषण प्रबंधन हेतु पोषण पुनर्वास केंद्र (NRC) के लिए रेफर किया गया।

स्वस्थ मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य का संदेश - इस अवसर पर निवाड़ी के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.सी. मलार्य एवं पृथ्वीपुर के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. गजेंद्र निरंजन ने उपस्थित गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, संतुलित एवं पौष्टिक

प्रदीप खरे एवं बीसोपम श्री फंज साहू का विशेष सहयोग रहा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से शिविर का सफल संचालन किया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने सभी गर्भवती महिलाओं से प्रत्येक माह आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (PMSMA) दिवस पर नियमित जांच करने एवं सुरक्षित मातृत्व की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की।

आहार, आयरन एवं कैल्शियम की दवाओं का नियमित सेवन, टी का करण तथा किसी भी गंभीर लक्षण के दिखाई देने पर तत्काल न ज दी की र वा र थ य संस्थान में चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की। शिविर के सफल संचालन एवं समन्वय में पृथ्वीपुर के वि का स खंड का य क्र म प्र बंध क श्री वामित श्री वा र त व निवाड़ी के वि का स खंड का य क्र म प्रबंधक श्री

बुजुर्गों और असहाय लोगों का आदर करना हमारा धर्म : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



निर्धन परिवार, वृद्धजन और दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें

सागर, प्रतिनिधि

निवाड़ी | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि घर में बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद होना, तपती धूप में ठंडी छांव के समान होता है। हमारी संस्कृति में बुजुर्गों, असहायों और समाज के सबसे कमजोर वर्ग को आदर देना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा धर्म माना गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य का कोई भी निर्धन परिवार, माताएं, बहनें या हमारे दिव्यांग साथी स्वयं को बेसहारा न समझें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंत्योदय का संकल्प सिद्ध हो रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार भी गरीबों, वींचितों और कमजोर वर्गों के कल्याण में जुटी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण के लिए मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में यह विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम से विभिन्न जिलों के हितग्राही वचुंअली जुड़े।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 33 लाख 92 हजार 695 से अधिक भाई-बहनों और बुजुर्गों के खातों

में माह मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, श्री संजय शुक्ला, श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव श्रीमती सोनाली वायंगणकर कार्यक्रम में उपस्थित थीं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सरकार के स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है - मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं है, अपितु निर्धन परिवारों, दिव्यांग साथियों में आपके प्रति सरकार का स्नेह, सम्मान और सुरक्षा का वचन है। राज्य सरकार सभी को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। सरकार प्रत्येक नागरिक के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कुषक कल्याण वर्ष में राज्य सरकार ने किसान हितैषी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा और इसे चुकाने की समयवधि 31 मार्च नहीं होगी, बल्कि किसान जिस तारीख को कर्ज लेंगे, उसे अगले 12 माह की अवधि में ऋण भरना होगा।

भारतीय हॉकी टीम में मध्यप्रदेश का बढ़ता प्रतिनिधित्व एक उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से पदक विजेता हॉकी खिलाड़ियों ने की मेटे

जापान में 29 मई से 06 जून तक हुआ था अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट



भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय हॉकी टीम में मध्यप्रदेश का बढ़ता प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश के खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने निवास पर भेंट के लिए आये अंडर-18 पुरुष और महिला हॉकी एशिया कप-2026 में पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। टूर्नामेंट का आयोजन जापान के काकागिमाहारा शहर में 29 मई से 06 जून 2026 तक किया गया था। पदक विजेता

पुरुष और महिला खिलाड़ियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन पर मध्यप्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी खेलों और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध

है। प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, नर्मदापुरम, सिवनी और बड़वानी के खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी बहुत साधारण परिवार से हैं। अपनी प्रतिभा के दम पर इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। निश्चित ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि

है। आने वाले एशियाई खेलों में इन खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश जो कभी हॉकी में कई ओलम्पियन दे चुका है, कुछ वर्ष इस खेल में पीछे रहा, लेकिन अब हरियाणा जैसे

राज्यों के समान अग्रणी हो रहा है।

खेल मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जापान में हुए टूर्नामेंट के लिए समीर दाद जैसे कोच खिलाड़ियों को दक्ष बनाने में लगे थे। अंडर-18 की श्रेणी में 6 पुरुष खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक और 4 महिला खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पदक विजेता खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनके साथ समूह छायाचित्र भी खिंचवाया। इस अवसर पर आयुक्त खेल एवं युवक कल्याण श्री संजीव कुमार सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अंडर-18 बालिका/महिला हॉकी एशिया कप में पुरुष वर्ग में एशिया के 9 देश (भारत, कोरिया, जापान, चीनी-ताइपे, कजाकिस्तान, मलेेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन) एवं महिला वर्ग में एशिया के 8 देश (भारत, कोरिया, मलेेशिया, सिंगापुर, चीन, जापान, चीनी ताइपे, बांग्लादेश) ने

भाग लिया।

प्रतियोगिता में भारत की 18 सदस्यीय बालक / बालिका हॉकी टीम ने भाग लिया।

भारतीय बालक हॉकी टीम में म.प्र. राज्य पुरुष हॉकी अकादमी, भोपाल के 06 बालक खिलाड़ी सदस्य रहे तथा स्वर्ण पदक अर्जित किया।

भारतीय बालिका हॉकी टीम में म.प्र. राज्य महिला हॉकी अकादमी, ग्वालियर की 04 बालिका खिलाड़ी सदस्य रही तथा कांस्य पदक अर्जित किया।

म.प्र. राज्य महिला हॉकी अकादमी की खिलाड़ी सुश्री नैसीन नाज ने प्रतियोगिता में 12 गोल कर टूर्नामेंट की 'टॉप स्कोरर' बनने का गौरव प्राप्त किया।

म.प्र. राज्य पुरुष हॉकी अकादमी के खिलाड़ी श्री आयुष रजक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'बेस्ट गोलकीपर अवार्ड' प्राप्त किया।

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ग बालक के हॉकी स्पर्ध पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 लाख प्रति खिलाड़ी एवं बालिका वर्ग के हॉकी कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को

एक लाख प्रति खिलाड़ी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है।

इन खिलाड़ियों ने किया प्रतिनिधित्व पुरुष खिलाड़ी :- श्री आयुष रजक, पिता स्व. अनिल रजक, जिला जबलपुर, स्वर्ण पदक। श्री अंश बहुजा, पिता श्री नीरज बहुजा, जिला नर्मदापुरम, स्वर्ण पदक। श्री करन गौतम, पिता श्री मनोज गौतम, जिला उमरिया, स्वर्ण पदक। श्री अवि माण्णुपि पिता श्री जितेन्द्र माण्णुपि, जिला भोपाल, स्वर्ण पदक। श्री सिद्धार्थ बेन, पिता श्री लेखराम बेन, जिला जबलपुर, स्वर्ण पदक। श्री गाजी खान, पिता श्री महबूब खान, जिला नर्मदापुरम, स्वर्ण पदक।

महिला खिलाड़ी:- सुश्री नैसीन नाज, पिता श्री अहफज खान, जिला सिवनी, कांस्य पदक। सुश्री महक परिहार, पिता श्री महरवान सिंह परिहार, कांस्य पदक। सुश्री स्नेहा दावडे, पिता श्री राजेश दावडे, जिला बड़वानी, कांस्य पदक। सुश्री नन्मी गीताश्री, पिता श्री नन्मी ताताराव, तिम्मापुरम, विशाखापट्टनम (आन्ध्रप्रदेश), कांस्य पदक।

65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नितिका आकरे ने जीता कांस्य पदक

पोल वॉल्ट स्पर्धा में 4.10 मीटर की छलांग के साथ एशियाई खेल 2026 के लिए किया क्वालीफाई



भोपाल | मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित एथलेटिक्स अकादमी की प्रतिभावान खिलाड़ी नितिका आकरे ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 24 से 28 जून 2026 तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन सायंकालीन सत्र में आयोजित महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में नितिका ने 4.10 मीटर की ऊंचाई

पर कर कांस्य पदक अर्जित किया। एशियाई खेल 2026 के लिए किया क्वालीफाई - नितिका आकरे ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एशियाई खेल 2026 के लिए निर्धारित क्वालीफिकेशन मानक भी हासिल कर लिया। महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में कुल तीन खिलाड़ियों

ने एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई किया, जिनमें नितिका भी शामिल रहीं। यह उपलब्धि उनकी निरंतर मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट प्रशिक्षण का परिणाम है।

राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की मजबूत उपस्थिति - राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने के साथ एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई करना मध्यप्रदेश की खेल प्रतिभाओं की बढ़ती क्षमता और खेल अकादमियों में उपलब्ध उच्च स्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था को दर्शाता है। नितिका की यह सफलता प्रदेश की महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायी है।

खेल मंत्री श्री विश्वास कैलाश

सारंग ने दी बधाई - खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नितिका आगामी एशियाई खेलों में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए मिसाल बनी नितिका - नितिका आकरे की यह उपलब्धि प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों, विशेषकर महिला एथलीटों के लिए प्रेरणास्रोत है। यह सफलता दर्शाती है कि प्रतिभा, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

आदेश पर आदेश फिर भी नहीं सुधरे बाइक सवार,हेलमेट नहीं पहनने पर 5 महीने में 10 हजार से ज्यादा चालान

भोपाल | सड़क हादसों में मौत और गंभीर चोटों को कम करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन लगातार हेलमेट पहनने को लेकर सख्ती बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजधानी के दोपहिया वाहन चालक अब भी नियमों को गंभीरता से नहीं ले रहे। हेलमेट अनिवार्य करने, 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' लागू करने और चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी करने जैसे कई फैसलों के बावजूद हालात नहीं बदले हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में बिना हेलमेट वाहन चालान पर 10,143 चालान काटे गए। ट्राफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मई 2026 के बीच राजधानी में कुल 27,152 चालान बनाए गए। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई हेलमेट नहीं पहनने वालों पर हुई। इस अवधि में 30.42 लाख रुपये का जुर्माना सिर्फ हेलमेट नियम तोड़ने वालों से वसूला गया। यानी हर तीन चालानों में लगभग एक चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का रहा।



एक साल में कई बार हुए सख्त फैसले - सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पिछले एक वर्ष में कई अहम कदम उठाए। 30 जुलाई 2025 को बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं देने का आदेश जारी किया गया। 1 अगस्त 2025 से राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 'नो हेलमेट-नो पेट्रोल' व्यवस्था लागू की गई। इसके बाद चालक के साथ पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया और विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी ड्यूटी के दौरान तथा दोपहिया वाहन चलाने समय अनिवार्य

रूप से हेलमेट पहनने के निर्देश दिए गए थे, ताकि आम लोगों के सामने पुलिस स्वयं उदाहरण पेश कर सके।

हेलमेट को लेकर सख्ती की बात तो लगातार की गई, लेकिन इसका चालन हर स्तर पर नहीं दिख रहा। राजधानी में आज भी कई पुलिसकर्मी दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट चलते नजर आ जाते हैं। ऐसे में आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। जब नियम लागू कराने वाली एजेंसी के कर्मचारी ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आम नागरिकों से पूरी तरह पालन की उम्मीद करना भी मुश्किल हो जाता है।

जल-जंगल-जमीन संरक्षण के लिए कांग्रेस ने गटित की विशेष समिति

भोपाल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों से जुड़े मुद्दों और जल, जंगल व जमीन के अधिकारों के संरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने एक विशेष उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश में आदिवासी समाज के हितों की रक्षा और उनसे जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी की आगामी रणनीति तय करेगी। आदिवासी द्वारा गठित इस समिति में पार्टी के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघाव को इस समिति में प्रमुख रूपा से शामिल किया गया है। उनके अलावा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह (राहुल भैया)



और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम भूरिया को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति मुख्य रूप से इन विषयों पर काम करेगी जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के पारंपरिक व संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन और इससे जुड़े जमीनी मुद्दों की समीक्षा। आदिवासी अंचलों में जमीन से जुड़े विवादों और हक की लड़ाई को लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक व सामाजिक रणनीति तैयार करना।

एमएस भोपाल के डॉ. विक्रम वट्टी ने अमेरिका में फेफड़ा प्रत्यारोपण का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया

भोपाल। एम्स भोपाल ने उन्नत चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के कार्डियो थोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. विक्रम वट्टी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में फेफड़ा प्रत्यारोपण (लंग ट्रांसप्लांट) संबंधी विशेष प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इस उपलब्धि से भविष्य में एम्स भोपाल में फेफड़ा प्रत्यारोपण सेवाओं को विकसित करने और गंभीर फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उन्नत उपचार उपलब्ध कराने का मार्ग और अधिक मजबूत होगा। यह प्रशिक्षण वेंडरबिल्ट लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के सर्जिकल निदेशक एवं विश्वप्रसिद्ध थोरेसिक सर्जन डॉ. कोनराड होएट्सेनेकर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी



मेडिकल सेंटर अमेरिका के प्रमुख फेफड़ा प्रत्यारोपण केंद्रों में शामिल है, जहां प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सफल प्रत्यारोपण किए जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान डॉ. वट्टी ने अंग प्राप्त प्रक्रिया, रोगी मूल्यांकन एवं चयन, फेफड़ा प्रत्यारोपण

सर्जरी, आधुनिक शल्य तकनीकों, बहु-विषयक टीम समन्वय तथा प्रत्यारोपण के बाद रोगियों की देखभाल जैसी उन्नत व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन किया। यह विशेषज्ञता एम्स भोपाल में भविष्य की लंग ट्रांसप्लांट सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक एवं सीईओ माधवानन्दकर ने इस उपलब्धि पर डॉ. विक्रम वट्टी को बधाई देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव संस्थान में विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा मरीजों को अत्याधुनिक उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वर्तमान में एम्स भोपाल को फेफड़ा प्रत्यारोपण सेवाएं प्रारंभ करने की अनुमति भी प्राप्त है, जिससे यह उपलब्धि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

आयुष्मान योजना से भोपाल के 91 अस्पताल बाहर अब 264 केंद्रों पर ही मिलेगा मुफ्त इलाज

डॉक्टर और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम की कमी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई अस्पतालों में निर्धारित मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।



योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भोपाल के 91 अस्पतालों को पैनल से बाहर (डी-एम्पैनल)

कर दिया है। जांच में इन अस्पतालों में अनियमितताएं, फर्जी क्लेम और मानकों की अनदेखी के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की

कार्रवाई के बाद अब भोपाल जिले में केवल 264 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के तहत मान्य रह गए हैं, जहां पात्र हितग्राही अपने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त और केशलेस इलाज का लाभ उठा सकेंगे। जांच में सामने आई गंभीर गड़बड़ाया विभाग द्वारा किए गए ऑडिट और औचक निरीक्षण के दौरान कई अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में पता चला कि कुछ निजी अस्पतालों ने अधिक भुगतान प्राप्त करने के लिए मरीजों को बिना आवश्यकता भर्ती किया और उपचार के नाम पर फर्जी या बड़े हुए क्लेम प्रस्तुत किए। कई मामलों में सामान्य बीमारियों के मरीजों को अनावश्यक

रूप से आईसीयू में भर्ती दिखाकर बड़ी राशि का दावा किए जाने की शिकायतें भी सही पाई गईं। डॉक्टर और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम की कमी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि कई अस्पतालों में निर्धारित मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ और लाइफ-सपोर्ट सिस्टम जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। कुछ अस्पताल ऐसे भी मिले जिन्होंने लंबे समय से किसी आयुष्मान कार्डधारक को सेवा ही नहीं दी थी। ऐसे संस्थानों को पात्रता समाप्त कर उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया। भोपाल में वर्तमान स्थिति स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, वर्तमान में भोपाल जिले में

आयुष्मान योजना के तहत 264 अस्पताल मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 235 निजी और 29 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इनमें से 136 अस्पताल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, जहां उपचार की गुणवत्ता राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाती है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर सख्ती से अंकुश लगाने से आयुष्मान योजना का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा।

सांभर को पोहा खिलाने के मामले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रभारी सहायक संचालक निलंबित

भोपाल | सोशल मीडिया पर वन्यजीव सांभर के साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्र संचालक ने प्रभारी सहायक संचालक इटारसी एवं प्रभारी अधीक्षक बोरी, विनोद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्यजीव सांभर को पोहा खिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। इसे वन्यजीवों

के साथ पालतू जानवरों के समान व्यवहार करने के आरोप लगे थे। इस मामले में शिकायत के बाद वन विभाग ने सख्त एक्शन लेकर संबंधित अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, वायरल वीडियो में विनोद वर्मा वन्यजीव (सांभर) के साथ अस्वाभाविक व्यवहार करते हुए



दिखाई दे रहे हैं। इसे शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही और असंवेदनशीलता माना गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि उनके इस कृत्य से मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन हुआ है। इसी आधार पर नियम के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहायक संचालक कार्यालय, पिपरिया (सतपुड़ा

टाइगर रिजर्व) निर्धारित किया गया है। उन्हें क्षेत्र संचालक की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय रहेगा। वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने कहा कि वन्यजीवों के साथ इस तरह का व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों को मानव संपर्क में लाना और उन्हें भोजन खिलाना उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति के विपरीत है। इससे न केवल उनके व्यवहार में बदलाव आता है, बल्कि

गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना है, न कि उन्हें भोजन देकर मानव पर निर्भर या पालतू जैसा बनाना। उन्होंने कहा कि इस मामले में की गई कार्रवाई आवश्यक है और इससे भविष्य में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से पालन करने का संदेश मिलेगा।

संपादकीय

वर्दी का भय या कानून का विश्वास ?

लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों, सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी आंकी जाती है कि आम नागरिक स्वयं को कितना सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस करता है। जब कोई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भयमुक्त होकर प्रश्न पूछ सकता है, तभी लोकतंत्र वास्तव में जीवंत माना जाता है। लेकिन कानून की रक्षा करने वाली संस्थाओं पर ही भय पैदा करने के आरोप लगने लगे, तब लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं।

गोड्डा जिले के मुफरिसल थाना क्षेत्र के लालपुर गाँव में 25 जून 2026 को सामने आई एक कथित घटना ने ऐसे ही अनेक सवाल को जन्म दिया है। आरोप है कि सादे वेश में कुछ पुलिसकर्मी बिना नंबर प्लेट वाले वाहन से गाँव पहुँचे और स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिसिया रैब दिखाया। आरोप यह भी है कि एक माल्यता प्राप्त पत्रकार द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाने के बाद भी कथित रूप से अग्रह व्यवहार किया गया। यद्यपि इन आरोपों की निष्पक्ष जाँच और पुलिस प्रशासन का पक्ष सामने आना अभी शेष है, फिर भी यह घटनाक्रम लोकतंत्र, पत्रकारिता और पुलिस जवाबदेही पर व्यापक चर्चा की माँग करता है।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या पत्रकार भीड़ का हिस्सा है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वह न सत्ता का प्रतिनिधि होता है और न ही विपक्ष का। उसका दायित्व जनता और शासन के बीच सूचना का सेतु बनना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, पत्रकार उसी अधिकार का सामाजिक विस्तार है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण से जुड़े पत्रकार पिछले लगभग तीन दशकों से देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। वे अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पत्रकार संगठनों, प्रेस एसोसिएशनों तथा पत्रकार मंचों से जुड़े रहे हैं और जनसरोकार, प्रशासनिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा ग्रामीण भारत से जुड़े विषयों पर लगातार लेखन करते रहे हैं। ऐसे में यदि किसी वरिष्ठ और माल्यता प्राप्त पत्रकार के साथ भी कथित रूप से अग्रह व्यवहार या धमकी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति की गरिमा का नहीं रह जाता, बल्कि पत्रकारों की कार्य-स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा से भी जुड़ जाता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक अवसरों पर कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। यदि पत्रकार भयमुक्त नहीं रहेंगे, तो जनता तक सत्य और सूचना का प्रवाह भी बाधित होगा। इसलिए किसी पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता से जुड़ा विषय बन जाता है।

दूसरी ओर यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। झारखंड जैसे राज्य में पुलिस की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण है। राज्य लंबे समय तक नक्सलवाद, संगठित अपराध, अवैध खनन, साइबर अपराध तथा सामाजिक तनावों जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। हाल के वर्षों में झारखंड पुलिस ने अपराध नियंत्रण और उपायवाद विरोधी अभियानों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की बरामदगी और साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं।

गोड्डा जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले में समय-समय पर अवैध हथियारों, आपराधिक गिरोहों, भूमि विवादों तथा संगठित अपराधों के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे हैं। ऐसे में पुलिस को कई बार चरित और संवेदनशील कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी कार्रवाई की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया से भी तय होती है।

यही वह बिंदु है जहाँ नागरिक अधिकारों और पुलिस शक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस पूछताछ करती है तो नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उससे पूछताछ करने वाला व्यक्ति कौन है और किस अधिकार के तहत कार्रवाई कर रहा है।

सवाल यह भी है कि यदि पुलिस सादे वेश में कार्रवाई कर रही हो तो उसकी पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आज के दौर में जब अपराधी भी स्वयं को पुलिस बताकर लोगों को ठगने लगे हैं, तब आम नागरिक के मन में संदेह होना स्वाभाविक है। इसलिए पारदर्शिता केवल नागरिक का अधिकार नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े बताते हैं कि झारखंड के सामने अपराध नियंत्रण की चुनौती अभी भी बनी हुई है। हत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और आर्थिक अपराध जैसी समस्याएँ राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को अधिक अधिकार और संसाधन मिलना चाहिए, लेकिन उतनी ही मजबूती से जवाबदेही की व्यवस्था भी सुनिश्चित होनी चाहिए।

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह सिद्धांत नागरिक पर भी लागू होता है और वर्दी पर भी। पुलिस की शक्ति संविधान से आती है, भय से नहीं। यदि किसी नागरिक या पत्रकार को यह महसूस हो कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, तो उसे शिकायत करने, जाँच की माँग करने और न्याय पाने का अधिकार है।

आज आवश्यकता पुलिस ब्रह्मण्य पत्रकार की बहस की नहीं है। आवश्यकता पुलिस और पत्रकार के बीच विश्वास बहाली की है। दोनों ही लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है और पत्रकार उस कार्रवाई को जनता तक पहुँचाता है। दोनों का लक्ष्य अंततः तान्त्रिक ही है।

यदि लालपुर की घटना में लगाए गए आरोप गलत सिद्ध होते हैं, तो इससे पुलिस की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। यदि कहीं किसी स्तर पर चूक या दुर्व्यवहार पाया जाता है, तो निष्पक्ष कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ेगा। दोनों ही परिस्थितियों में सत्य, पारदर्शिता और विधि का शासन ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है।

झारखंड पुलिस के हजारों अधिकारी और जवान कठिन परिस्थितियों में दिन-रात सेवा दे रहे हैं। उनके योगदान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उतना ही आवश्यक यह भी है कि आम नागरिक, पत्रकार और समाज के कमजोर वर्ग स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। लोकतंत्र में वर्दी का सम्मान और नागरिक की गरिमा—दोनों साथ-साथ चलते हैं।

कानून का राज केवल अपराधियों को पकड़ने से स्थापित नहीं होता। कानून का राज तब स्थापित होता है जब आम आदमी बिना भय के अपने अधिकारों का उपयोग कर सके, पत्रकार बिना डबाव के प्रश्न पूछ सके और पुलिस बिना पक्षपात के कानून लागू कर सके।

गोड्डा की यह कथित घटना चाहे जिस निष्कर्ष तक पहुँचे, उसने एक महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़ा किया है—क्या हम भय आधारित व्यवस्था चाहते हैं या विश्वास आधारित शासन?

लोकतंत्र का उत्तर स्पष्ट है। वर्दी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन संविधान केवल भी ऊपर है। पत्रकार का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वह जनता की आवाज है। और सबसे बढ़कर, आम नागरिक का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही लोकतंत्र का वास्तविक स्वामी है।

जब वर्दी में संवेदनशीलता होगी, कलम में निष्पक्षता होगी और नागरिक के मन में विश्वास होगा, तभी झारखंड की कानून-व्यवस्था वास्तव में मजबूत मानी जाएगी। यही लोकतंत्र की आत्मा है, यही संविधान की भावना है और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति भी।

मोबाइल की लत में खोती याददाश्त : एक गंभीर चेतावनी

वर्तमान डिजिटल युग में मोबाइल फोन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। संचार, शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, खरीदारी और सामाजिक संपर्क जैसे लगभग सभी कार्य अब मोबाइल के माध्यम से संपन्न होने लगे हैं। तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक अवश्य बनाया है, किंतु इसके अंधाधुंध उपयोग ने अनेक नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। इनमें सबसे चिंताजनक समस्या है—मोबाइल की बढ़ती लत और उससे प्रभावित होती मानव स्मरण शक्ति अर्थात् याददाश्त।

आज का दृश्य अत्यंत सामान्य हो गया है कि लोग अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों अथवा सहकर्मियों के मोबाइल नंबर तक याद नहीं रखते। जन्मदिन, महत्वपूर्ण तिथियाँ, आवश्यक सूचनाएँ और यहाँ तक कि दैनिक कार्यों की सूची भी मोबाइल पर निर्भर हो गई है। परिणामस्वरूप मस्तिष्क की स्वाभाविक स्मरण क्षमता का उपयोग लगातार कम होता जा रहा है। जिस कार्य के लिए पहले व्यक्ति अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता था, अब वही कार्य मोबाइल फोन कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब हम किसी जानकारी को स्वयं याद रखने के बजाय मोबाइल में सुरक्षित कर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को लंबे समय तक संग्रहित करने का प्रयास नहीं करता। धीरे-धीरे यह आदत स्मृति क्षमता को कमजोर करने लगती है। मोबाइल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को भूलने लगता है और उसकी एकाग्रता भी प्रभावित होती है।

मोबाइल की लत का सबसे अधिक दुष्प्रभाव बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। घंटों तक सोशल मीडिया, वीडियो गेम, शॉर्ट वीडियो और मनोरंजन सामग्री देखने के कारण उनका ध्यान पढ़ाई से भटक रहा है।



निरंतर स्क्रीन देखने से मस्तिष्क को पर्याप्त विश्राम नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाना, ध्यान केंद्रित न कर पाना और मानसिक थकान जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विद्यार्थी किसी तथ्य को समझने या याद रखने के बजाय तुरंत इंटरनेट पर खोज लेते हैं। इससे उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता तथा स्मरण शक्ति का विकास बाधित होता है। परीक्षा के समय ऐसे विद्यार्थियों को विषयवस्तु याद रखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

मोबाइल की अत्यधिक लत केवल याददाश्त को ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, संदेश और सोशल मीडिया अपडेट मस्तिष्क को हर समय सक्रिय रखते हैं। इससे तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याएँ बढ़ने लगती हैं। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद न मिलने से स्मरण शक्ति और अधिक कमजोर

हो जाती है। परिवारिक जीवन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पहले परिवार के सदस्य करते थे और विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के विकास और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होती थी। आज परिवार के अनेक सदस्य एक ही कमरे में बैठकर भी अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। संवादहीनता का यह वातावरण मानसिक विकास के लिए चिंता का विषय है।

मोबाइल की लत से बचने के लिए संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल-मुक्त गतिविधियों के लिए निर्धारित करना चाहिए। पुस्तक पढ़ना, लेखन करना, पहलियाँ हल करना, गणितीय अभ्यास करना, कविता याद करना, शारीरिक व्यायाम और ध्यान-योग जैसी गतिविधियाँ स्मरण शक्ति को सुदृढ़ बनाती हैं। बच्चों के स्क्रीन टाइम पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए तथा उन्हें

रचनात्मक और बौद्धिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना चाहिए।

विद्यालयों और अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को तकनीक के लाभों के साथ-साथ उसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता के साथ डिजिटल अनुशासन की शिक्षा समय की मांग है।

निष्कर्षतः मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की आवश्यकता है, किंतु आवश्यकता और निर्भरता के बीच की सीमा को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम तकनीक के स्वामी बनने के बजाय उसके गुलाम बन जाएंगे, तो हमारी स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए आवश्यक है कि मोबाइल का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए, ताकि तकनीक हमारे विकास का साधन बने, हमारी क्षमताओं के ह्रास का कारण नहीं।

• सत्य भूषण शर्मा
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

और कितने 'लाक्षागृह'

यह अनिक्कांड नहीं, हत्याकांड है। यह हादसा या दुर्घटना नहीं, कत्लेआम का बंदोबस्त है। यह आधुनिक दौर का 'लाक्षागृह कांड' है। ऐसी हत्याएँ यहाँ नहीं रूकेंगी, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था बदली या बुलडोजर चलाए गए? देश में और कितने ऐसे 'लाक्षागृह' हैं, कोई नहीं बता सकता। ईश्वर भी असहाय साबित होंगे। जांच के नाम पर कुछ ढोंग किए जाते हैं, कुछ इमारतें सील की जाती हैं, छोटे कर्मचारी निलंबित कर दिए जाते हैं, बसहो गया न्याय। सरकारें मुआवजे बांटने को लालायित रहती हैं। शाब्द उनसे भी वोट मिलते होंगे! सरकारें अवैध, अतिक्रमण वाले, असुरक्षित, बिन अगिनशमन सिस्टम के, बड़े-बड़े निर्माणों, इमारतों, होटलों, मॉल, अस्पताल, स्कूल-कॉलेज की तर्फ आँख उठा कर भी नहीं देखतीं, क्योंकि 'चाय-पानी' मिल चुका होता है।

हमारी संपूर्ण व्यवस्था ही बेईमान, भ्रष्ट, नालायक और सुन्यावस्था में है। नलीजनत 'लाक्षागृह' बनते जा रहे हैं। लखनऊ में भी कुछ अधिकारियों को निलंबित करने से कुछ नहीं होगा। जिनके कार्यकाल में ये 'लाक्षागृह' बनाए गए हैं, उन्हें सरकारी सेवाओं से, तुरंत प्रभाव से, बर्खास्त कर देना चाहिए। सरकारें अदालती चुनौतियों को भी झेलें और उन्हें यथार्थ से अवगत कराएं।

सरकारों को ऐसा दंडात्मक रख अखिबार करना पड़ेगा। 'लाक्षागृह' में आग लगने से 2005-15 में सालाना 17,700 से अधिक मौतें हुईं हैं। 2015-24 के दौरान 10,909 मौतें! अर्थात् 25-30 'लाक्षागृह मीठ' हरोगे! कितना खौफनाक, त्रासद आँकड़ा है यह? 2024 की रपट भी सामने है, जिसके मुताबिक उस साल 5971 'लाक्षागृह कांड' हुए, जिनमें 5888 मौतें हुईं। क्या ऐसा देश 'विश्व-गृह' होने की खुशफहमी भी पालने लायक है? 'स्मार्ट सिटी' बनाने की परियोजना ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा ढाँचा बनाने में अक्षम हैं। हम चेतना-सोच के स्तर पर 'स्मार्ट' होने से बहुत दूर हैं। क्यों आदिताओं के करोड़ों रूपए 'स्मार्टफहमी' के नाम पर फूँके जा रहे हैं? जिन्हें 'चाय-पानी' की लार परेशान कर रही है, उन्हें सत्ता और प्राधिकरण के दफ्तरों से बाहर कर देना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यह काम नहीं कर सकते, तो यह काम भी देश की आक्रोशित जनता कर सकती है। यह लापरवाही, अनदेखी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि 70 फीसदी से अधिक दिल्ली 'लाक्षागृह' की आशंका, अदेशों के साथ जी रही है। जरा दिल्ली के स्वर बाजार, चांदनी चौक, करोल बाग, पहाड़ांज सरीखे बाजारों में घूम कर अनुभव लें।

टेक्नोलॉजी

एक पल भी बंद नहीं होगा इंटरनेट,

यहां बनेगी भारत की पहली डेटा सेंटर सिटी

तेलंगाना में देश की पहली डेटा सेंटर सिटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद से लगभग 55 किलोमीटर दूर Aloor गाँव में इसके लिए 1500 एकड़ जमीन की पहचान की है। इस सिटी में सरदेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रीटेड वॉटर सप्लाई और ओपन एक्सेस पावर आदि सुविधाओं के जरिए बड़ी कंपनियों को डेटा सेंटर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बता दें कि एआई आने के बाद से कंपनियाँ एआई डेटा सेंटर पर भारी निवेश कर रही हैं और दुनियाभर में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है।

क्यों बनाई जा रही है डेटा सेंटर सिटी? - अगर यह प्रोजेक्ट सिरि चढ़ता है तो तेलंगाना में देश की पहली डेटा सेंटर सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। डेटा सेंटर के लिए जगह की बढ़ती माँग को देखते इसे तैयार किया जाएगा। इन्फो डेटा सेंटर के लिए जरूरी सारी सुविधाएँ पहले



यहां बनेगी देश की पहली डेटा सेंटर सिटी

से ही मौजूद होंगी। यानी करीब 1500 एकड़ में बनने वाली इस सिटी में सिर्फ बड़ी इमारतें ही नहीं होंगी बल्कि यहां पावर हाउस, हाई-स्पीड फाइबर नेटवर्क, खुली सड़कें, कूलिंग के लिए पर्याप्त पानी की सप्लाई और सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाएगा ताकि कंपनियों को अपने स्तर पर इनका इंजायम न करना पड़े और उन्हें डेटा सेंटर शुरू करने के लिए सारी जरूरी चीजें एक ही जगह

मिल जाएं। क्या होगा डेटा सेंटर सिटी की खासियत? - एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए डेटा सेंटर बिना रुके काम करते हैं। डेटा सेंटर में लगे सर्वर को काम करने के पावर और ठंडा रहने के लिए पानी आदि की जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए इस सिटी में शहर से निकलने वाले पानी को ट्रीट कर यूज किया जाएगा।

सिटी में हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए फाइबर नेटवर्क का यूज किया जाएगा। डेटा सेंटर के काम को देखते हुए यहां लगातार इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी और यह सिटी एक पल के भी ऑफलाइन नहीं होगी। क्या डेटा सेंटर अब बनने लगे हैं? - कई लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या डेटा सेंटर अब बनने लगे हैं? इसका जवाब है कि डेटा सेंटर कई सालों से मौजूद हैं, लेकिन एआई आने के बाद इनकी जरूरत बढ़ी है और अब हर बड़ी कंपनी और देश एआई डेटा सेंटर बनाने पर जोर दे रहा है। मौजूदा दौर की बात करें तो ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जनरेटिव एआई ऐपस, रियल टाइम एनालिटिक्स और क्लाउड-बेस्ड मशीन लर्निंग सर्विसेस आदि के लिए उच्च मूल्यवस्था, सात्विक भोजन पूरी तरह से ट्रस्ट की तर्फ से दिया जाता है। इसके अलावा उनके और उनके परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सेवाएँ और हफ्तों में एक साप्ताहिक अवकाश भी दिया

जनरल नॉलेज

राम मंदिर के पुजारियों को कितनी पगार देते हैं चंपत राय, खुद कितनी है उनकी सैलरी?



अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मंदिर में चढ़ावे और चंदे में वित्तीय गड़बड़ी की खबरों ने जम्कर सुर्खियों बटोरी हैं। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी और चौंकार देने वाली खबर सामने आ रही है कि विवाद की आंच सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह हाई-प्रोफाइल इस्तीफा इस वक्त सुर्खियों में है। लेकिन इसी क्रम में यह भी जान लेते हैं कि आखिर चंपत राय राम मंदिर के पुजारियों को कितनी सैलरी देते थे और उनकी खुद की तनख्वाह कितनी थी।

राम मंदिर के मुख्य और सहायक पुजारियों की सैलरी - राम मंदिर परिसर के अंदर धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और रामलला की सेवा की कमान उनके सहायकों के हाथों में होती है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार, मंदिर में मुख्य पुजारी को हर महीने करीब 38,500 रुपये सैलरी मिलती है। वहीं उनके काम में हाथ बंटाने वाले सहायकों और पूजा-पाठ संचालने वालों को जिम्मेदारी और अनुभव के आधार पर ही हर महीने 33,000 से लेकर 36,000 रुपये तक का भुगतान किया जाता है।

सैलरी के साथ और कौन सी सुविधाएँ मिलती हैं? - मुख्य पुजारियों और सहायकों को सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि अन्य कई सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। रामलला की अनवरत सेवा में जुटे इन पुजारियों को अयोध्या में रहने के लिए उच्च मूल्यवस्था, सात्विक भोजन पूरी तरह से ट्रस्ट की तर्फ से दिया जाता है। इसके अलावा उनके और उनके परिवार के लिए बेहतरीन मेडिकल सेवाएँ और हफ्तों में एक साप्ताहिक अवकाश भी दिया

जाता है। भंडार और मैनेजमेंट संचालने वालों की कमाई - धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा इतने बड़े मंदिर परिसर में दैनिक रख-रखाव, लॉजिस्टिक्स, भंडार गृह की व्यवस्था को संचालने के लिए बड़ा स्टाफ काम करता है। इस ढाँचे के तहत भंडार, राशन और जरूरी सामग्री की देखरेख करने वाले लोगों को शामिल किया जाता है। ट्रस्ट के नियम के अनुसार इन पदों पर तैनात कर्मचारियों को हर महीने 19,000 से लेकर 24,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है।

दानपात्र और चढ़ावे की गिनती करने वालों की पगार - राम मंदिर में बड़ी भारी मात्रा में भक्तों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु सोना-चांदी, हीरा-मोती, रुपया-पैसा सबकुछ दान करते हैं। ऐसे में दानपात्रों से निकलने वाली रकम की गिनती, सिक्कों को अलग करना और उनका पूरा वेरिफिकेशन का काम निजी एजेंसियों और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए योग्य कर्मचारियों को दिया गया है। इनको हर महीने कबो 20,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाते हैं।

महासचिव चंपत राय की कितनी है सैलरी? - अब बात करते हैं उस पद की जो इस पूरे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह करते हैं, यानि चंपत राय। मंदिर के प्रशासनिक कार्य, जमीन से जुड़े मामले, मीडिया को जानकारी देना और कानूनी व्यवस्था संचालना यह सब इनका काम है। इस्तीफा देने के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में चंपत राय ही हैं, लेकिन खबरों की मानें तो चंपत राय इस पद के लिए एक रुपये भी सैलरी नहीं लेते हैं। राम मंदिर में वे एक पूर्णकालिक स्वयंसेवक के रूप में बिना किसी मासिक वेतन के सेवा कर रहे हैं।

पाकिस्तान को मिला पश्चिम एशिया में बड़ा मंच ? शशि थरूर का दावा भारत के कूटनीतिक संतुलन को लगा झटका

एजेंसी नई दिल्ली

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पश्चिम एशिया में 107 दिनों तक चले संघर्ष के बाद उभरे भू-राजनीतिक हालात पर अपना ओपिनियन रखा है। उन्होंने कहा है कि इस संघर्ष ने आधुनिक वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों को सामने ला दिया है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता (MoU), जिसे अगले 60 दिनों में शांति समझौते में बदलने की कोशिश होगी, फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत लेकर आया है। तेल आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और ब्रेट कूटनीतिक कीमते युद्धकालीन स्तर से नीचे आ रही हैं, लेकिन इस संघर्ष ने रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर कई नए सवाल भी खड़े किए हैं।

थरूर ने लिखा कि इस संघर्ष में अमेरिका अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल नहीं कर सका, जबकि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी रणनीतिक पकड़ बनाए रखी। वहीं, इजरायल ने क्षेत्रीय समूहों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ईरान को पूरी तरह झुकाने में सफल नहीं हुआ। उनके अनुसार, इन घटनाओं के समानांतर दक्षिण एशिया में भी कूटनीतिक भूमिकाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 'भारत अपनी पारंपरिक संतुलित नीति से भटकता दिखा' कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया में गैर-गुटीय और बाद में मल्टी-अलाइनमेंट की नीति अपनाई, जिसके तहत ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के साथ समान रूप से संबंध बनाए रखे गए। लेकिन हालिया संघर्ष के दौरान भारत अमेरिका-इजरायल धुरी के अधिक करीब दिखाई दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल अवीव यात्रा के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि इस कारण भारत की पारंपरिक तटस्थ छवि प्रभावित हुई।



‘भारत ने संभावित मध्यस्थ की भूमिका खो दी’ थरूर के अनुसार, किसी भी संघर्ष में जब एक संभावित मध्यस्थ पीछे हटता है तो उसकी जगह कोई दूसरा देश ले लेता है। उन्होंने लिखा कि भारत की कूटनीतिक स्थिति के कारण पश्चिम एशिया में शांति वार्ता, विशेषकर जेनेवा में होने वाली चर्चाओं में पाकिस्तान को अधिक प्रमुख भूमिका मिलती हुई दिखाई दी। उनके मुताबिक, यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए एक महत्वपूर्ण झटका माना जा सकता है। ‘पाकिस्तान केवल संदेश पहुंचाने वाला माध्यम था’ अपने लेख में थरूर ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद ने खुद को शांति स्थापित कराने वाले देश के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उसके पूरे आचरण से वह निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं बल्कि अमेरिका के प्रति अत्यधिक झुकाने वाले सहयोगी दिखाई दिया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से कथित रूप से वॉशिंगटन में तैयार बयान जारी करने की घटना का

एक माध्यम चाहिए था। इस लिहाज से पाकिस्तान ने एक ‘डिप्लोमैटिक सरगेट’ की भूमिका निभाई। ‘भारत को फिर मजबूत करनी होगी रणनीतिक स्वायत्तता’ लेख में थरूर ने कहा कि पश्चिम एशिया का यह संघर्ष भारत के लिए बड़ा सबक है। उनके अनुसार, किसी एक पक्ष के करीब दिखने से वैश्विक मंच पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने की क्षमता कमजोर होती है। इसलिए भारत को अपनी पारंपरिक मल्टी-अलाइनमेंट और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को फिर से मजबूत करना चाहिए। थरूर ने निष्कर्ष में लिखा कि अंतिम शांति समझौता होने पर पाकिस्तान, कतर, ओमान जैसे देशों को कूटनीतिक प्रयासों के लिए सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका को स्वतंत्र वैश्विक नेतृत्व के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि दुनिया एक स्वतंत्र कूटनीतिक शक्ति और केवल संदेश पहुंचाने वाले देश के बीच अंतर को अच्छी तरह समझती है।

भारत के चिकन नेक तक चीन की एंट्री, तीस्ता नदी पर बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान ने की बड़ी डील

एजेंसी बीजिंग



बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर में एक बार फिर भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल, बीजिंग के दौर पर गए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन के साथ तीस्ता नदी परियोजना पर बड़ा समझौता किया है। बांग्लादेश और चीन तीस्ता समेत कई दूसरी नदियों के मैनेजमेंट में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह समझौता चीन के जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ बीजिंग के दियाओयुताई स्टेट गेस्ट हाउस में हुआ। मुलाकात के दौरान, प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन के मंत्री को बांग्लादेश में चल रही नदी खुदाई कार्यक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का मकसद बांग्लादेश में बाढ़ के खतरों को कम करना, पर्यावरण को रक्षा करना और जल संसाधनों का सही मैनेजमेंट सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस परियोजना में और बांग्लादेश में दूसरी नदियों के मैनेजमेंट के काम में चीन से मदद की मांग की। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने तीस्ता मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में चीन से तकनीकी मदद भी मांगी। इसके जवाब में, चीनी मंत्री ने जल संसाधन मैनेजमेंट में बांग्लादेश सरकार की पहलों में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। 2005 में बांग्लादेश और चीन के बीच हुए समझौता जापान (MoU) और पिछले साल चीनी जल विशेषज्ञों के बांग्लादेश दौरे का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि जल संसाधन मैनेजमेंट में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग व्यावहारिक और रिसर्च पर आधारित है। तीस्ता परियोजना में चीन के शामिल होने से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। तीस्ता नदी सिक्किम में हिमालय से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र (जमुना) नदी में मिल जाती है।

तीस्ता नदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब से गुजरती है। यह 20 किमी चौड़ी और 60 किमी लंबी जमीन की एक पतली पट्टी है, जिसे ‘चिकन नेक’ के नाम से भी जाना जाता है। अगर चीन यहां तक पहुंचता है, तो पूर्वोत्तर में भारत की चिंता बढ़ सकती है। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद है। बांग्लादेशी पक्ष के मोसम में तीस्ता नदी के पानी का 50 प्रतिशत हिस्सा मांगता है, जबकि 2011 के एक मसौदे के अनुसार, भारत को 42.5% और बांग्लादेश को 37.5% पानी देने का प्रस्ताव था। भारतीय संविधान के अनुसार, जल संसाधन राज्य का विषय है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के लगातार विरोध के कारण भारत-बांग्लादेश में तीस्ता नदी को लेकर समझौता नहीं हो सका है। बांग्लादेश की तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापना परियोजना (TRCMRP) एक प्रमुख ढांचगत और वाटर मैनेजमेंट पहल है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सूखे के दौरान पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तीस्ता बेसिन का मैनेजमेंट करना है। इस परियोजना की लागत 1 अरब डॉलर आंकी गई है। परियोजना के अंतर्गत 102 किलोमीटर लंबी नदी की खुदाई की जाएगी जिससे पानी के बहाव को सुनिश्चित होगा।

बदलती हकीकत को स्वीकार करें स्थापित ताकतें... जयशंकर ने दक्षिण कोरिया से अमेरिका को खूब सुनाया

एजेंसी सिंगल

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सिंगल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिका का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। उन्होंने देशों के बीच ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन को “जिरो-सम गेम” (एक की जीत, दूसरे की हार) के तौर पर देखने की बढ़ती आदत के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ स्थापित ताकतों को बदलती वैश्विक हकीकत के साथ तालमेल बैठाने में मुश्किल हो रही है। उनका निशाना सीधे तौर पर अमेरिका की ओर था, जिसने न केवल भारत के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, बल्कि ईरान पर हमला कर पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। दक्षिण कोरिया के जेजू में ‘शांति और समृद्धि के लिए 21वें जेजू फोरम’ में मुख्य भाषण देते हुए जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक उथल-पुथल अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा समृद्धि के विचार के लिए एक चुनौती है। जयशंकर ने कहा, “कुछ स्थापित ताकतों को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता (कॉम्पिटिटिवनेस) खोने को स्वीकार करने में मुश्किल होती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय



अर्थव्यवस्था एक ‘जिरो-सम गेम’ बन जाती है।” उन्होंने ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के सिद्धांत का जिक्र किया, जिसका मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है। जयशंकर ने कहा, “भारत में हम जानते हैं कि पारंपरिक रूप से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के तहत दुनिया एक परिवार है। आज हमारे आस-पास जो उथल-पुथल दिख रही है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि समाज में कुछ ताकतें इसी विश्वास को चुनौती दे रही हैं।”

उन्होंने बार-बार अधिक संतुलित और मल्टीपोलर वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। जयशंकर का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय फैसलों को आकार देने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी भूमिका होनी चाहिए, जिसे दुनिया वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ का नाम देती है। भारत और अमेरिका के संबंधों में लंबे समय से तनाव है। यह तनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में काफी ज्यादा बढ़ा है। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया और बाद रूसी तेल खरीद के कारण टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया, जो दुनिया में सबसे ज्यादा था। बाद में ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होने के बाद इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया। ट्रंप लगातार पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं और उसके कुख्यात सेना प्रमुख असीम मुनिर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बता रहे हैं।

वेनेजुएला तो सिर्फ ट्रेलर... दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली भूकंप, एक में तो 280000 मौतों का रिकॉर्ड

एजेंसी काराकस

वेनेजुएला में धरती डोली और अपने साथ बर्बादी लेकर आई। एक झटके में कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। हालांकि ये भूकंप वेनेजुएला के इतिहास के सबसे बड़े झटकों में शामिल हैं, लेकिन दुनिया में अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों की सूची में इनकी जगह नहीं बन पाई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूसएजीएस) की आधिकारिक साइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दुनिया का सबसे शक्तिशाली दर्ज भूकंप वर्ष 1960 में चिली के बायोबियो क्षेत्र में आया था। इस भूकंप की तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इसे ‘ग्रेट चिली भूकंप’ के नाम से जाना जाता है। इस विनाशकारी भूकंप में करीब 1,655 लोगों की मौत हुई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप- 1964 इस सूची में दूसरा बड़ा नाम वर्ष 1964 के अलास्का भूकंप का है, जिसकी



तीव्रता 9.2 थी। यह भूकंप करीब चार मिनट तक महसूस किया गया था और इससे अलास्का सहित आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ। इस आपदा में लगभग 130 लोगों की जान गई थी। दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा भूकंप- 2004 वर्ष 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा क्षेत्र में आया 9.1 तीव्रता का भूकंप दुनिया की सबसे दर्दनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गया। समुद्र के भीतर आए इस भूकंप ने विनाशकारी सुनामी

को जन्म दिया, जिसने भारत सहित कई देशों के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस आपदा में 2.8 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भूकंप- 2011 वर्ष 2011 में जापान के तोहोकु क्षेत्र में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप ने आधुनिक दुनिया को झकड़कर दिया। इस भूकंप के बाद आई सुनामी ने जापान के कई हिस्सों को प्रभावित किया और 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। दुनिया के पांचवें और छठे सबसे बड़े भूकंप- 1952, 2025 रूस के कामचटका क्षेत्र में भी दो बड़े भूकंप दर्ज किए गए। इनमें 100 साल का अंतर था। वर्ष 1952 में आए भूकंप की तीव्रता 9.0 थी, जिसमें करीब 15,000 लोगों की मौत हुई। वहीं, वर्ष 2025 में इसी क्षेत्र में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप में किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं थी। दुनिया का सातवां सबसे बड़ा भूकंप- 1950 भारत का नाम भी इस फेहरिस्त में शुमार है। आजादी के महज तीन साल बाद, वर्ष 1950 में अरणाचल प्रदेश में आए 8.6 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इसमें करीब 780 लोगों की मौत हुई थी।



अमेरिका ने भारत को AMCA फाइटर जेट पर फंसाया, 80 करोड़ का इंजन 200 करोड़ डिमांड! गलती किसकी

एजेंसी वॉशिंगटन

भारत जल्द से जल्द और हर हाल में एडवांस्ड मीडियम कॉन्वैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बनाना चाहता है। ये प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। लेकिन इस विमान के इंजन को लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनी GE ने अपने F414 इंजन की कीमत पहले के अनुमानों की तुलना में तीन गुना बढ़ाकर बताई है। इसके साथ ही GE ने भारत में इंजन की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करने के लिए भी हजारों करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत की मांग की है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच नई कीमत के आने के बाद बावचीत रूक गई है। इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ व्यापारिक मोलभाव है या जियो-पॉलिटिकल गेम। AMCA लड़ाकू विमान के इंजन के इंजन को लेकर शुरू हुए विवाद को लेकर भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट और एविएशन आर्किटेक्ट विजयेन्द्र के ठाकुर और भारत के एक लड़ाकू विमान इंजन प्रोजेक्ट में सीनियर लेवल पर काम कर रहे

सौरव झा से खस बात की है। हमने F414 इंजन की नई कीमत और भारत के पास अब क्या विकल्प हैं इन सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश की। दोनों एक्सपर्ट्स से हुई बातचीत के आधार पर इस विश्लेषण रिपोर्ट को लिखा गया है। फिलहाल AMCA के शुरुआती प्रोटोटाइप के लिए अमेरिकी GE F414 इंजन को चुना गया है। यही इंजन तेजस Mk-2 में भी लगाया है। लेकिन अब कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों को लेकर बातचीत में रुकावट आने की रिपोर्ट है। हालांकि सरकार और GE की ओर से सार्वजनिक रूप से सभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन रक्षा क्षेत्र में चर्चा है इंजन की नई कीमत बताई गई है वो काफी ज्यादा है। बातचीत रूकने से प्रोजेक्ट की समयसीमा और रणनीतिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विजयेन्द्र के ठाकुर ने कहा कि भारत का प्लान प्रोटोटाइप में GE F414 इंजन लगाकर टेस्ट करना है। अगर कामयाबी मिलती है तो फिर विमान में कोई और इंजन लगाकर फाइनल विमान बनाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये रणनीति ही गलत है। क्योंकि इंजन के आधार पर एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं ना कि एयरक्राफ्ट के आधार पर इंजन। उन्होंने कहा कि GE F414 इंजन की कीमत बढ़ाने के पीछे

ये वजह हो सकता है कि भारत का ऑर्डर काफी कम हो। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि भारत GE F414 इंजन को तेजस Mk-2 और नौसेना के TEBDF लड़ाकू विमान में लगाया चाहता है और 200 इंजन खरीदने की मंशा रखता है। लेकिन दिक्कत ये है कि तेजस Mk-2 प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है और TEBDF प्रोजेक्ट तो फाहलों में ही है। तो फिर 200 इंजन खरीदने की संभावना भी सवाल में है। अमेरिका सिर्फ इंजन की कीमत बढ़ा रहा या फंसा रहा है? फिलहाल पहली संभावना पूरी तरह व्यावसायिक लग रही है लेकिन जियो पॉलिटिकल वजह से भी इनकार नहीं है। सौरव झा का मानना है कि वैश्विक रक्षा उद्योग में सप्लाय चेन लागत, महंगाई, उत्पादन क्षमता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। GE जैसी कंपनियों अक्सर प्रोडक्शन लागत बढ़ाने, लाइसेंसिंग और स्पॉनोरिशन के लिए अलग लागत मांगती हैं। उन्होंने कहा कि AMCA के टेस्टिंग फेज के लिए Rolls Royce EJ 200 और नए Safran M88 T-REX वर्शन (हालांकि यह वर्शन अभी साबित नहीं हुआ है) पर ऑफर के तौर पर एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं ना कि एयरक्राफ्ट के आधार पर इंजन को अपनाने के लिए डिजाइन में बदलाव करने होंगे।

हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले भरी हुंकार, याद कराई पिछले साल की हार, जख्मों पर छिड़का नमक



नई दिल्ली, एजेंसी | महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने चौथे मुकामले में बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर भारतीय टीम ने सेमीफाइनल की उम्मीदों को मजबूत कर लिया है। अगले चरण में जगह पक्की करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को मात देना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका से हार झेलने के बाद यह भारत के लिए करो या मरो मुकामला होने वाला है। इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया को चेता दिया है। उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड कप में कंगारू टीम के खिलाफ जीत का जिक्र किया है।

हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया को लेकर दिया वयान

हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकामले से पहले

हुंकार भर दी है। उन्होंने वर्ल्ड कप 2025 में नवी मुंबई के मैदान पर मिली जीत को याद करते हुए कहा कि टीम इंडिया की खिलाड़ियों का आत्म विश्वास बढ़ा हुआ है। हरमन ने कहा, 'उनके खिलाफ हुए आखिरी मैच में हमने जीत दर्ज की थी। इससे सभी खिलाड़ियों के आत्म विश्वास बढ़ा हुआ है। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे परसदीदा टीमों में से एक है। उम्मीद करती हूँ कि सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट खेल दिखाएँ और हम जीतने वाली साइड पर हों।'

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के टी20 फॉर्मेट में हेड टू हेड की बात कर तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमों के बीच

अब तक 38 टी20 मुकामले खेले जा चुके हैं। जिसमें से कंगारू टीम ने 27 बार नतीजा अपने पक्ष में किया है। जबकि भारते खते में सिर्फ 9 जीत आई है। इस दौरान एक मैच बेनतीजा भी रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया अब तक अपराजित है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए उनकी चुनौती से पार पाना आसान नहीं होगा।

कब और कहां खेला जाएगा मैच ?

इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत रविवार यानि 28 जून को होने वाली है। लंदन का ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान इस टक्कर का गवाह बनने वाला है। भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे मुकामले की पहली गेंद फेंकी जाएगी। इससे पहले 6:30 बजे टॉस होगा।

आयरलैंड से पहली बार हारा भारत, श्रेयस अय्यर की शर्मनाक शुरुआत; 17 साल का दबदबा खत्म

नई दिल्ली, एजेंसी | आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार है जब आयरलैंड ने टीम इंडिया को हराया है। बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की बहुत खराब शुरुआत हुई है, क्योंकि वो पहली बार टी20 में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आयरलैंड द्वारा मिले 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 148 रनों पर सिमट गई। पिछले 17 साल में आयरलैंड ने पहली बार भारत को टी20 मैच में हराया है। भारतीय टीम की यह हार इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि वह



पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी भी नहीं कर पाई। भारतीय टीम 7 गेंद पहले ही ऑलआउट हो गई। टीम इंडिया के लिए केवल अभिषेक शर्मा ही

बड़ी पारी खेल पाए, जिन्होंने 20 गेंद में 50 रनों की तूफानी पारी खेली। अभिषेक ने इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए।

17 साल में पहली जीत

टी20 क्रिकेट के इतिहास में भारत और आयरलैंड का सबसे पहला मैच 2009 में हुआ था। उसके बाद पिछले 17 साल में दोनों टीम 8 बार भिड़ चुकी थीं, लेकिन हर बार टीम इंडिया एकतरफा अंदाज में जीतती आ रही थीं। मगर 26 जून 2025 की तारीख आयरलैंड टीम हमेशा याद रखेगी, क्योंकि इसी दिन टी20 में उसका भारत के खिलाफ हार का सूखा समाप्त हुआ।

श्रेयस अय्यर की शर्मनाक शुरुआत

टी20 फॉर्मेट में अब तक एम्पस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुर्यकुमार यादव भारतीय टीम के फुल-टाइम कप्तान रहे हैं। श्रेयस अय्यर टी20 टीम के पांचवें फुल-टाइम कप्तान बने हैं, लेकिन उनके कप्तानी करियर की शुरुआत बहुत खराब रही।

पहले ही मैच में उस भारतीय टीम को हार मिली, जो कुछ महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर आ रही है। अय्यर व्यक्तिगत रूप से भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। उन्होंने 7 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाए।

आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप: भारत ने 7 गोल्ड के साथ जीते कुल 24 मेडल

नई दिल्ली, एजेंसी | भारत ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 24 मेडल अपने नाम किए। जर्मनी के सुह्ल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। भारत के अभियान की शुरुआत जबरदस्त रही। सेजल कांबले ने 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस जूनियर इवेंट में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता, जबकि हिमांशी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। इसके बाद सेजल कांबले, वंशिका चौधरी और नव्या बिश्नोई की तिकड़ी ने इसी इवेंट के टीम मुकामले में गोल्ड मेडल जीतकर चैंपियनशिप में भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई।

समीर ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष जूनियर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जबकि रोहित कन्या 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन पुरुष जूनियर प्रतियोगिता में विजेता बने। प्राची गायकवाड ने 50 मीटर राइफल



3 पोजिशन महिला जूनियर इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इनके अलावा, भारत ने लगातार अच्छा टीम प्रदर्शन करते हुए 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन पुरुष जूनियर टीम और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। अन्वी राठौड़ ने 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा, जिसके बाद प्रीतम केंद्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। भारत ने 25 मीटर पिस्टल पिस्टल जूनियर टीम और 25 मीटर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीते और स्टैंडिंग में अपनी टॉप पोजिशन को और मजबूत किया। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर

कैटेगरी में, शिवा नरवाल ने सिल्वर और युग प्रताप सिंह राठौड़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शानदार डबल-पोइंडियम फिनिश हासिल की। इसके बाद नरवाल ने संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा के साथ मिलकर टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता, जिसके बाद वंशिका चौधरी के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ट टीम इवेंट में एक और सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत का सबसे मजबूत प्रदर्शन चैंपियनशिप के आखिरी दौर में देखने को मिला। अभिनव देशवाल ने 25 मीटर स्टैंडिंग पिस्टल पुरुष जूनियर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, जबकि शाश्वती श्रवण क्षीरसागर और अभिनव शां ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ट टीम जूनियर मुकामले में गोल्ड मेडल हासिल किया।

यूएस ओपन 2026: रौनक चौहान ने वर्ल्ड नंबर 6 चाउ टिएन चैन को हराकर त्वाटर फाइनल में जगह बनाई

नई दिल्ली, एजेंसी | भारत के रौनक चौहान ने गुवरु को यहां यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे बड़ा उलटफेर किया। रौनक ने वर्ल्ड नंबर 6 और पुरुष एकल में टॉप सीड चीनी ताइपे के चाउ टिएन चैन को सीधे गेम में हरा दिया।

दुनिया के 80वें नंबर के खिलाड़ी चौहान भारत के कांस्य पदक जीतने वाले वर्ल्ड जूनियर कैपेन का हिस्सा थे। चौहान ने चाउ को 21-17, 26-24 से हराकर इजरायल के मिशा जिल्बर्मेन के खिलाफ आखिरी आठ में जगह बनाई। 18 साल के भारत के खिलाड़ी ने शुरू से ही अपने से ज्यादा अनुभवी विरोधी पर दबाव बनाए रखा। हालांकि, चाउ 17-15 तक आगे रहे, लेकिन इसके बाद चौहान ने लगातार छह पॉइंट जीतकर पहला गेम अपने नाम कर लिया।

दूसरे गेम में ज्यादातर समय चाउ हावी रहे और उन्होंने 17-11 की बढ़त बना ली। चौहान ने



एक बार फिर से वापसी की और लगातार छह पॉइंट लेकर बराबरी कर ली। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों में जीत के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली। चौहान ने चार गेम पॉइंट बचाए और फिर अपना दूसरा मैच पॉइंट बदलकर 49 मिनट में जीत हासिल की।

दूसरे गेम में ज्यादातर समय चाउ हावी रहे और उन्होंने 17-11 तक आगे रहे, लेकिन इसके बाद चौहान ने लगातार छह पॉइंट जीतकर पहला गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे गेम में ज्यादातर समय चाउ हावी रहे और उन्होंने 17-11 की बढ़त बना ली। चौहान ने

व्यापार

1 जुलाई से क्या-क्या बदल जाएगा? लागू होने वाले नए नियमों का आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?

नई दिल्ली, एजेंसी | हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम साथ लाती है। जून का महीना अब बस खत्म होने को है और जुलाई का महीना शुरू होने की कगार पर है। भारत में 1 जुलाई 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम (India financial rule changes July 2026) बदल रहे हैं, जिनका ग्राहकों और करदाताओं पर सीधा असर होगा। इन नए नियमों में UPI से PF की निकासी से लेकर डीए में बढ़ोतरी, LPG की कीमतों में बदलाव जैसी कई चीजों के होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं 1 जुलाई 2026 से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं।

IIR फाइल करने की डेडलाइन - नौकरीपेशा और बिना ऑडिट वाले टेक्सपेयर्स के लिए सैलरीड इनकम टैक्स रिटर्न (IIR-1 और IIR-2) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। यानी कि सैलरी पाने वाले कर्मचारी और वे लोग

जिनकी इनकम कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी या एसी दूसरी नॉन-बिजनेस इनकम से होती है जिसके लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें IIR-1 और IIR-2 फॉर्म भरने होंगे।

HDFC क्रेडिट कार्ड के बदलेंगे नियम - 1 जुलाई से नए वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही शुरू हो रही है। इस मौके पर HDFC Bank ने अपने Regalia Gold और Diners Club Privilege क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। पहले लागू हो चुके कुछ बदलावों के अलावा 1 जुलाई 2026 से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नए नियम लागू होंगे कुछ बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं, जबकि 1 जुलाई 2026 से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नए नियम लागू होंगे।



1 जुलाई से होने वाले बड़े बदलाव

नए नियम के अनुसार, 1 जुलाई से HDFC बैंक Regalia Gold क्रेडिट कार्ड यूजर्स को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस पाने के लिए हर तिमाही में खर्च की एक नई सीमा पूरी करनी होगी। इस पॉलिसी के तहत, ग्राहकों को अगली तिमाही में मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60000 रुपये खर्च करने होंगे।

LPG, CNG और PNG की कीमतों में संभावित बदलाव - हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करेगी। इस दौरान घरेलू और कर्माश्रित सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही एयर टर्बाइन फ्यूल के लिए भी नए टैरिफ लागू होंगे।

जाएंगे, जिसका हवाई जहाजों की टिकट की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा।

UPI निकाला जा सकेगा PF - 1 जुलाई से UPI से PF निकालना ATM से कैश निकालने जितना आसान हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के जुलाई में अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 को लॉन्च करने की उम्मीद है। इस सुविधा के शुरू होने के साथ EPFO सबक्राइबर्स UPI के जरिए अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद PF का पैसा निकालने में कुछ दिन नहीं, बल्कि चंद्र मिनट लगेंगे।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा - विदेश मंत्रालय ने एक दशक से भी अधिक समय के बाद पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से लागू नए नियमों के तहत, 36- पेज के नए या री-इश्यू पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगी। यानी कि सीधे 1000 रुपये की

बढ़ोतरी की गई है। वहीं, तत्काल सर्विस के लिए अब पहले के 3500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे। 60- पेज के जंबो पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाकर 6000 रुपये तक कर दी जाएगी।

रेलवे पेनल्टी के नियमों में बदलाव - 1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर डबल जुर्माना देना होगा। नए नियमों के तहत, जुर्माने की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा रहा है। साथ ही अब से अगर कोई पुरुष महिला कोच में सफर करते हुए पाया गया, तो उस पर 2500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

फ्री में अपडेट होगा आधार - UIADAI ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से अगले छह महीने के लिए आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया है। पहले आधार में नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल बदलने के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे

बढ़ोतरी की गई है। वहीं, तत्काल सर्विस के लिए अब पहले के 3500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे। 60- पेज के जंबो पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाकर 6000 रुपये तक कर दी जाएगी।

रेलवे पेनल्टी के नियमों में बदलाव - 1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर डबल जुर्माना देना होगा। नए नियमों के तहत, जुर्माने की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा रहा है। साथ ही अब से अगर कोई पुरुष महिला कोच में सफर करते हुए पाया गया, तो उस पर 2500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

फ्री में अपडेट होगा आधार - UIADAI ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 1 जुलाई से अगले छह महीने के लिए आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया है। पहले आधार में नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल बदलने के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे

क्रिसिल की राहत भरी रिपोर्ट, लेकिन चेताया- मिडिल ईस्ट सीजफायर नाजुक, कंपनियों पर खतरा बना हुआ है

नई दिल्ली, एजेंसी | अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम कायम रहने और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहने से पश्चिम एशिया संघर्ष का भारतीय कंपनियों के लाभ पर पड़ने वाला असर शुरुआती आशंका की तुलना में लाभग आधा रह जाएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स ने यह जानकारी दी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि यह संघर्ष वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय कंपनियों के परिचालन मुनाफे में लगभग एक प्रतिशत की कमी लाएगा। पहले लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने और होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही बाधित होने की स्थिति में दो प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया था।

संशोधित अनुमान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-ईरान के बीच हुए नाजुक समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य दोबारा खुलने से कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। हालांकि, क्रिसिल ने आगाह किया कि भू-राजनीतिक जोखिम अब भी बने हुए हैं और गैस आपूर्ति को पूरी तरह सामान्य होने में अधिक समय लग सकता है। क्रिसिल रेटिंग्स के प्रबंध निदेशक सुबोध राय ने कहा, 'यदि युद्धविराम कायम रहता है, तो हमारे आकलन वाले 34 क्षेत्रों में से दो-तिहाई का न्यूनतम अपर पड़ेगा। पहली छमाही के दबाव की भरपाई दूसरी छमाही में मुनाफे में सुधार से काफी हद तक हो जाएगी। हालांकि, संघर्ष बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। इसलिए हमारा मानना है कि भारतीय कंपनियां सतर्क रहेंगी और आपूर्ति शृंखला में विविधता लाने पर ध्यान देती होंगी।'

क्रिसिल के 34 क्षेत्रों पर आधारित इस आकलन में यह पाया गया कि चालू वित्त वर्ष में ब्रेंट कच्चे तेल का औसत भाव 80-85 डॉलर प्रति बैरल रहेगा और गैस आपूर्ति में उर्वरक विनिर्माता ऊर्जा कीमतों में नरमी के सबसे बड़े लाभार्थियों में शामिल हो सकते हैं। क्रिसिल के अनुमान हैं कि मार्च और मई के बीच सरकारी ईंधन ख़ुदरा विक्रेताओं को 40,000-45,000 करोड़ रुपये की शुद्ध कम वसूली का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ चालू वित्त वर्ष में उनके फ़िर से परिचालन लाभ में लौटने की उम्मीद है। बेहतर परिदृश्य के बावजूद, क्रिसिल ने दो प्रमुख जोखिमों की ओर इशारा किया है। पहला, अमेरिका-ईरान के बीच हुआ अंतरिम एवं गैर-बाध्यकारी समझौता, जिसके कारण संघर्ष दोबारा भड़कने की आशंका बनी हुई है। दूसरा, अंतर नीली की स्थिति विकसित होने का खतरा, जिससे मानसून कमजोर पड़ सकता है और ग्रामीण मांग प्रभावित हो सकती है।

वैश्विक संकट के बीच भारत बना सेफ-हेवन, टेक कंपनियों ने की 90 अरब डॉलर निवेश की घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी | भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक व्यवधानों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद वैश्विक कंपनियों तथा संस्थागत निवेशकों ने हाल के महीनों में भारत में 90 अरब डॉलर से अधिक के नए निवेश की घोषणा की है। यह भारत की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं और निवेश गंतव्य के रूप में उसकी बढ़ती वैश्विक साख को दर्शाता है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित निवेश कृत्रिम मेधा (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल अवसंरचना, विनिर्माण और औद्योगिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे वैश्विक कंपनियों के लिए आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाने तथा उच्च वृद्धि

वाले बाजारों में विस्तार के बीच अहम निवेश गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

अमेजन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एंडी जेसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद कंपनी ने ब्रह्मसंविदा को कहा कि वह वर्ष 2030 तक भारत में अपने कुल निवेश की प्रतिबद्धता बढ़ाकर 48 अरब डॉलर करेगा। यह निवेश क्लाउड अवसंरचना, एआई और डिजिटल सेवाओं के विस्तार में किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की डेटा सेंटर कंपनी एयरटंक ने 2030 तक भारत में पांच गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने के लिए 30 अरब डॉलर निवेश करने की योजना की घोषणा की थी। यह देश में



अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अवसंरचना निवेशों में से एक है। फ्रांस की निर्माण सामग्री से जुड़ी कंपनी सेंट-गोबेन ने 18 जून को कहा था कि वह अगले पांच वर्षों में भारत में अतिरिक्त एक अरब यूरो (1.15 अरब डॉलर) का निवेश करेगी। कंपनी ने भारत को अपने सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजारों में से एक बताया।

क ना डा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) ने भी सीटीआरएलएसए के डाटासेंटर्स के साथ मिलकर हाइपरस्केल डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये तक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं औद्योगिक प्रौद्योगिकी कंपनी एबीबी ने मार्च में भारत में अपने विनिर्माण और अनुसंधान नेटवर्क के बाजार के रूप में देख रही है। सूत्रों ने बताया कि हालिया निवेश प्रतिबद्धताएं भारत की दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं में वैश्विक

कंपनियों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती हैं। इसके पीछे देश का विशाल घरेलू बाजार, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर होती अवसंरचना और विदेशी निवेश आकर्षित करने की नीतियां प्रमुख कारण हैं। निवेश घोषणाओं की यह शृंखला दर्शाती है कि भारत वैश्विक पूंजी के लिए तेजी से आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय निवेशक आर्थिक तथा भू-राजनीतिक विस्तार का प्रमुख केंद्र मान रही हैं। सूत्रों ने कहा कि इन सभी निवेश प्रतिबद्धताओं से स्पष्ट है कि वैश्विक आर्थिक तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत पर अपना दांव और मजबूत कर रही हैं।



प्रियंका चोपड़ा जोनसन ने की 'ऑब्सेशन' की तारीफ

कहा- हॉलीवुड में अवसरों की दीवारें टूट रही हैं

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनसन ने निर्माता बनने और अमेरिका में अपने करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा पर खुलकर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि अब हॉलीवुड में नए कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रवेश की बाधाएं पहले की तुलना में काफी कम हो गई हैं। प्रियंका ने कम बजट की सफल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि आज के दौर में प्रतिभाशाली लोगों के लिए अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। बुधवार को आयोजित कैस लायंस सम्मेलन में शामिल हुई प्रियंका ने कहा, 'मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई अच्छा विचार है तो आप उसे शूट कर सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं और वह 'ऑब्सेशन' जैसी फिल्म बन सकती है, जो हाल ही में रिलीज हुई है।' उन्होंने आगे कहा, 'मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए यह बेहद शानदार समय है, क्योंकि आज के दौर में विचार ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।' प्रियंका ने बताया कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब हालात इतने आसान नहीं थे। पिछले एक दशक से हॉलीवुड में अपना करियर बना रही अभिनेत्री ने कहा कि शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका फिल्मी दुनिया से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा, 'मेरे माता-पिता डॉक्टर थे, इसलिए हममें से किसी को भी यह नहीं पता था कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है। जब मैंने शुरुआत की थी, तब यह बहुत सीमित और खास लोगों तक पहुंच वाला क्षेत्र था। अगर आपको

फिल्म निर्माण में आना होता था तो पहले यह तय करना पड़ता था कि आप किस विभाग में काम करना चाहते हैं। प्रियंका ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें बताया गया था कि भारतीय सिनेमा कभी हॉलीवुड जितना वैश्विक नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारतीय फिल्में अंग्रेजी भाषा में नहीं होतीं। उन्होंने कहा, 'मुझे बताया जाता था कि भारतीय सिनेमा कभी हॉलीवुड जितना वैश्विक नहीं होगा, क्योंकि हमारी फिल्में अंग्रेजी में नहीं बनतीं और हर कोई हिंदी, तेलुगु, मराठी या अन्य भारतीय भाषाओं को नहीं समझता।' अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस इसलिए शुरू किया ताकि नए फिल्मकारों और उन रचनात्मक लोगों को मंच मिल सके, जिनके पास बेहतरीन विचार तो हैं, लेकिन उद्योग के दरवाजे खोलने के लिए जरूरी संसाधन या संपर्क नहीं हैं। प्रियंका ने कहा, 'मैं ऐसे नए फिल्मकारों का समर्थन करना चाहती हूँ जिनके पास शानदार विचार हैं, लेकिन उनके पास उन अवसरों तक पहुंच नहीं है, जिन तक मैं उन्हें पहुंचाने में मदद कर सकती हूँ।' हाल ही में स्ट्रीमिंग हिट्स सिटाडेल और हेड्स ऑफ स्टेट का हिस्सा रही प्रियंका ने अपने अंग्रेजी भाषा के करियर को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, 'हिंदी सिनेमा में मैंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम किया है। मैंने कई शानदार कहानियां और अलग-अलग शैलियों की फिल्मों की हैं। लेकिन अमेरिका और हॉलीवुड में अपने अंग्रेजी भाषा के काम में मुझे अभी वैसी विविधता और अवसर उतने नहीं मिले हैं।' प्रियंका का मानना है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और कोविड-19 महामारी के दौरान बदली दर्शकों की आदतों ने दुनिया भर की सामग्री को नए दर्शक दिए हैं। उनके अनुसार, अब लोग विभिन्न देशों और भाषाओं की कहानियों को पहले से कहीं ज्यादा अपनाने लगे हैं, जिससे वैश्विक मनोरंजन उद्योग में नई संभावनाएं पैदा हुई हैं।

हॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकॉन्स अवॉर्ड्स में सितारों का जलवा, ग्लैमर और फैशन का दिखा शानदार संगम



मुंबई में आयोजित इस प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, अनन्या पांडे, आयुष्मान खुराना, नुसरत बरूचा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शरवरी वाघ, पुलकित सम्राट, भूमि पेडनेकर, मानुषी छिल्लर, राधिका मदान, मनुषी वाणी कपूर, वेदांग रैना और हेली शाह सहित कई नामचीन सितारों ने शिरकत की और अपने आकर्षण से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।

रेड कार्पेट पर सितारों के शानदार फैशन का जलवा देखने को मिला। किसी ने अपनी क्लासिक और एवरग्रीन स्टाइल से प्रभावित किया तो किसी ने मॉडर्न और ट्रेंडी लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ग्लैमरस आउटफिट्स में सजे सितारों ने कैमरों के सामने

जमकर पोज दिए और मीडिया से बातचीत कर इस खास शाम को और भी यादगार बना दिया।

यह समारोह सिर्फ एक अवॉर्ड शो नहीं था, बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मनोरंजन जगत में लगातार बदलते फैशन ट्रेंड्स का भी उत्सव था। फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की कई प्रभावशाली हस्तियां एक ही मंच पर नजर आईं, जिससे पूरे आयोजन का माहौल उत्साह और ऊर्जा से भर गया।

ग्लैमर, स्टाइल और मनोरंजन के बेहतरीन मेल के साथ 'हॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकॉन्स अवॉर्ड्स' ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है।

गौरतलब है कि यह मंच उन ट्रेंडसेटर्स और कलाकारों को सम्मानित करता है, जो अपने फैशन सेंस और शानदार अभिनय से लगातार दर्शकों को प्रेरित करते रहते हैं।

'हॉलीवुड हंगामा स्टाइल आइकॉन्स अवॉर्ड्स' फैशन, ग्लैमर और स्टार पावर का एक मध्य उतसव बनकर उभरा, जहां मनोरंजन जगत के कई बड़े सितारों ने अपनी मौजूदगी से शाम को यादगार बना दिया।

अब दर्शकों को एक अलग रजत बेदी देखने को मिलेगा

जन्मदिन पर अभिनेता का लोगों से वादा



'कोई... मिल गया', 'जोड़ी नंबर 1', 'इंडियन', 'रक्त' और 'पार्टनर' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता रजत बेदी ने बुधवार को अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस खास अवसर पर उन्होंने आईएनएस से बात की और अपनी जिंदगी, करियर, फिटनेस और बदलते मनोरंजन जगत को लेकर विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि आने वाला समय उनके लिए काफी खास रहने वाला है और दर्शकों को जल्द ही उनका एक नया रूप देखने को मिलेगा। आईएनएस ने जब उनसे पूछा कि क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव रहा है, जिसने सब कुछ बदल दिया हो, तो रजत बेदी ने कहा, 'मुझे इस साल ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब तक मैंने जिन किरदारों को निभाया है, आने वाले समय में उनसे बिल्कुल अलग भूमिकाएं करने वाला हूँ। कुछ ऐसे सपने थे जिन्हें मैं पहले पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन अब उन्हें साकार करने का मौका मिल रहा है। मेरा वादा है कि आने वाली फिल्मों में दर्शकों को एक बिल्कुल अलग रजत बेदी देखने को मिलेगा।' अभिनेता ने कहा, 'इस समय मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा है और मेरे भीतर काम को लेकर एक नई ऊर्जा है। पहले मैंने इंडस्ट्री में कुछ मौके खोए थे, लेकिन अब नए किरदारों के जरिए दर्शकों का दिल जीतना चाहता हूँ।' इंडस्ट्री में करियर बनाने आ रहे नए कलाकारों को सलाह देते हुए रजत बेदी ने कहा, 'किसी को भी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। इसका जो हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। एक समय ऐसा था, जब मैं दूसरों की बातों में आकर खुद को मायूस करने लगता था। अब मैंने सीख लिया है कि जीवन में सबसे जरूरी अपनी सोच और अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना है। मैं भविष्य में वही करूंगा, जो मेरा दिल कहेगा और दूसरों की राय को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा।' रजत बेदी ने कहा, 'मैंने सलमान खान, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है, और ये सभी मेरे लिए खास रहे हैं। लेकिन अगर सबसे पसंदीदा कलाकार की बात करें तो संजय दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। वह बेहद साफ दिल के इंसान हैं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। संजय दत्त के साथ बिताए गए पल आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं।' सोशल मीडिया के दौर में कलाकारों की निजी जिंदगी पर लगातार नजर रखे जाने के सवाल पर रजत बेदी ने कहा, 'मैं मानता हूँ कि आज के समय में सितारों की निजी जिंदगी पहले के मुकाबले काफी कम रह गई है। अब लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कोई भी छोट्टी या बड़ी बात बहुत जल्दी इंटरनेट पर पहुंच जाती है और लोगों के बीच फैल जाती है। हालांकि सोशल मीडिया के कई सकारात्मक पहलू भी हैं। सोशल मीडिया की वजह से कलाकार सीधे फैंस से जुड़े रहते हैं और लोगों के बीच उनकी मौजूदगी बनी रहती है। इसके कुछ नुकसान होने के बावजूद इसके फायदे भी कम नहीं हैं।' रजत बेदी ने युवाओं को स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा महत्व देने की सलाह दी। उन्होंने कहा, 'अच्छी सेहत जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए रोजाना व्यायाम करें और अपने खानपान पर खास ध्यान दें। भोजन में पौष्टिक और स्वस्थ चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है।

'सुपर सुबू' में ह्यूमर और सच्ची मानवीय भावनाओं का बेहतरीन संतुलन है: मिथिला पालकर

अभिनेत्री मिथिला पालकर अपनी आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज सुपर सुबू की रिलीज की तैयारी में हैं। अभिनेत्री का कहना है कि इस सीरीज में उनका किरदार हास्य और वास्तविक मानवीय भावनाओं के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करता है। बुधवार को सीरीज का ट्रेलर जारी किया गया। इसमें सुदीप किशन और मुरली शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी सुब्रमण्यम 'सुबू' चिल्लुकुरी राव के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पोस्टिंग काल्पनिक गांव माकीपुर में होती है, जहां कोई भी शिक्षक जाना नहीं चाहता। सुबू अपने परिवार के सामने सम्मान बनाए रखने के इरादे से गांव पहुंचता है और पढ़ाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे गांव में सबसे असहज जिम्मेदारी यानी सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का काम सौंप दिया जाता है।

सीरीज में अपने किरदार को लेकर मिथिला पालकर ने कहा, 'मुझे 'सुपर सुबू' की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि यह हास्य के साथ-साथ वास्तविक मानवीय भावनाओं को भी खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। तमाम अफरा-तफरी, जिज्ञासा और हंसी-मजाक के पीछे रिश्तों, स्वीकार्यता और एक-दूसरे को बेहतर ढंग से समझने की कहानी छिपी हुई है। निर्देशक मल्लिक राम ने जो दुनिया रची है, वह अनोखी, जीवंत और ऊर्जा से भरपूर है। इस यात्रा में हर किरदार कुछ यादगार लेकर आता है।'

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसी कहानी का हिस्सा बनना जो मनोरंजक होने के साथ-साथ सार्थक भी हो, मेरे लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा। नेटफ्लिक्स के साथ काम करना हमेशा घर वापसी जैसा महसूस होता है। मैं उनके शुरुआती ओरिजिनल शो लिटल थिंग्स का हिस्सा रही हूँ और अब उनकी पहली तेलुगु ओरिजिनल सीरीज 'सुपर सुबू' से जुड़ना ऐसा लगता है जैसे यह सफर पूरा चक्र पूरा कर चुका हो। मैं दुनिया भर के दर्शकों के

माकीपुर के आकर्षण को देखने के लिए उत्साहित हूँ। वहीं अभिनेता सुदीप किशन ने कहा, "'सुपर सुबू' एक ऐसे विषय को उठाती है, जिस पर लोग अक्सर खुलकर बात करने से झिझकते हैं। लेकिन यह इसे हास्य, गर्मजोशी और ईमानदारी के साथ पेश करती है। सुबू एक ऐसा व्यक्ति है जो एक समस्या सुलझाने निकलता है और अनजाने में पांच नई समस्याओं में फंस जाता है। नौकरी की परेशानियों, रिश्तों की उलझनों, पिता के सामने अपनी छवि बचाने की कोशिश और गांव वालों को नाराज कर देने जैसी स्थितियों के बीच वह लगातार मुश्किलों में घिरा रहता है। उसकी सबसे खास बात यह है कि उसकी नीयत हमेशा अच्छी रहती है, भले ही हालात उसके नियंत्रण से बाहर क्यों न हो जाएं।'

उन्होंने कहा, 'माकीपुर अजीबोगरीब लेकिन दिलचस्प किरदारों से भरा हुआ है और हर गलतफहमी कहानी में नया हास्य और नया बवाल जोड़ती है। दर्शक लगातार यह सोचते रहेंगे कि सुबू अब इस स्थिति से कैसे निकलेगा। इतनी शानदार स्टारकास्ट के साथ काम करना और नेटफ्लिक्स की पहली तेलुगु ओरिजिनल सीरीज का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि दर्शक सुबू से मिलें और उसकी इस यादगार यात्रा का हिस्सा बनें।'

मल्लिक राम, रमेश एलिंगेटी और शिवानी डोबाल द्वारा लिखित इस सीरीज का निर्माण राजीव चिलाका और भरत लक्ष्मीपति ने चिलाका प्रोडक्शंस के बैनर तले किया है। यह सीरीज हास्य, भावनाओं और छोटे शहरों की परिचित उथल-पुथल को एक अनोखी कर्मिंग-ऑफ-एज कहानी के रूप में पेश करती है। 'सुपर सुबू' 2 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।



महिला अधिवक्ताओं की समस्याओं को दूर करना हमारा कर्तव्य - अधिवक्ता अमृतलाल

साधना एक्सप्रेस सतना

सतना अधिवक्ता संघ की कार्यकारणी निर्वाचन में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतलाल शुक्ला ने साथी अधिवक्ताओं के साथ अपने प्रचार-प्रसार के दौरान कहा कि महिला अधिवक्ताओं के सामने आने वाली दिक्कतों पर भी ध्यान देना हम सबका दायित्व है। उन्हें अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा अदालत परिसर में बिताना पड़ता है। उस पर उनके आराम, प्राइवैसी, सुरक्षा और काम-काज के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का होना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री शुक्ला ने कहा कि कुछ दशकों में कानूनी पेशे में महिलाओं की भागीदारी में



लागतार उल्हासजनक बढ़ती हुई है। महिला अधिवक्ताओं की इस भागीदारी को सार्थक बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करना जरूरी है, जिससे उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से, सुरक्षित रूप से और बराबरी के स्तर में निभाने में मदद मिल सके। उन्होंने पुनः जोर देकर कहा कि जूनियर महिला/पुरुष अधिवक्ताओं को शुरूआती वर्षों के संघर्ष से बचाने के

लिए वजीफा और वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाना एक बड़ा दायित्व है जिसे हर हाल में निभाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों में युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रोफेशनल असिस्टेंट्स फंड स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वकालत न छोड़नी पड़े। आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग हमें मिला तो युवा महिला/पुरुष अधिवक्ताओं के सामने आने वाली वित्तीय चुनौती जैसी गंभीर समस्या का निराकरण हम सब मिलकर करने का प्रयास करेंगे। इन सभी कार्यों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल का गुणवत्ता पूर्ण निर्माण बेहद जरूरी है जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।

नरसिंहपुर पुलिस की मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी

» थाना गाडरवारा पुलिस की बड़ी कार्यवाही,
» स्लैक पाउडर सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार,
साधना एक्सप्रेस नरसिंहपुर



लगभग 02 लाख 75 हजार रुपए कीमती 27.50 ग्राम स्मैक जपत, गाडरवारा। (राजेश नीरस) पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीना के द्वारा जिले में अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध "OPERATION EAGLE CLOW" चलाया जा रहा है।

इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर संदीप भूरिया एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) गाडरवारा, ललित सिंह डागपुर के मार्गदर्शन में थाना गाडरवारा पुलिस की टीम के द्वारा 24 जून की रात्रि करीबन 23.25 बजे शमशान घाट के पास गाडरवारा

में संदेही के कब्जे से 27.50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर जपत किया गया है।

नाम आरोपी :- शंख मजीद पिता शंख हकीम

उम्र 52 वर्ष, निवासी- नरसिंह वार्ड करेली थाना करेली जिला नरसिंहपुर जन्मी :- आरोपी के कब्जे से 27.50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर कीमती लगभग 2,75,000/- रुपए जपत किया गया है।

वैधानिक कार्यवाही :-

आरोपी- शंख मजीद के विरुद्ध धारा 8,21(b),स 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कार्यवाही में सराहनीय भूमिका:- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी गाडरवारा निरीक्षक-अशोक सिंह चौहान के साथ उप निरीक्षक गजराज सिंह ठाकुर, वरिष्ठ आरक्षक- महेन्द्र बावोरिया, रूपेन्द्र चौबे, आरक्षक- नंदकिशोर, दिनेश पटेल, नीलेश दुबे, अक्षय श्रीवास्तव, सुजल भार्गव एवं महिला आरक्षक कुमुद पाठक साइबर सेल की विशेष भूमिका रही।

शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण से वेंटिलेटर पर पहुंची शिक्षा व्यवस्था

साधना एक्सप्रेस भोपाल

शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सर्व समाज और देश के भविष्य का निर्माण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। या कहा जाए कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। किन्तु दुर्भाग्य है कि आज देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि मानो देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी हो और इसके लिए जिम्मेदार लोग मुकदर्याक और तमाशाबाने बने हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते बाजारीकरण, शिक्षा माफियाओं का वर्चस्व, परीक्षाओं में चोटाले, पेपर लीक, फर्जी डिग्रियां और भ्रष्टाचार से युवाओं के सपनों को लगातार कुचला जा रहा है।



रहते हैं। नर्सिंग चोटाला, फर्जी कॉलेजों की मान्यताएं, निरीक्षण में भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाएं, नीट परीक्षाएं, पेपर लीक और शिक्षा संस्थानों की मनमानीयों ने पूरे शिक्षा तंत्र को कठपुतले में खड़ा कर दिया है। विगत वर्ष हुए नर्सिंग चोटाले में 50 से अधिक अकाल मृत्यु इसका एक जीवंत उदाहरण है। जब वह मंजर याद आता है तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजिमी हो जाता है। पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाने की साजिशें खुलेआम चल रही हैं। योग्यता, मेहनत और प्रतिभा को दरकिनार कर धनबल और प्रभाव के आधार पर युवाओं को अवसर बांटे जा रहे हैं। यह स्थिति न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर भी सीधा आघात कर रही है।

वर्तमान परिवेश में शिक्षा सेवा का भाव नहीं, बल्कि करोड़ों-अरबों रुपये का कारोबार बनता जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में शिक्षा के नाम पर भारी-भरकम फीस वसूली जा रही है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जहां एक ओर कर्ज लेने को मजबूर हैं, लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद छात्रों को न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और न ही रोजगार की गारंटी। वहीं अमीर-चंदों की बिगडैल औलादों को शिक्षा प्राप्त करना और डिग्रियां हासिल करना महज एक खिलौना बन गया है। इतना ही नहीं कई संस्थानों में गरीब और होनहार विद्यार्थियों को डिग्री के नाम पर केवल कागज का टुकड़ा भूमि दिया जाता है, जिसका व्यावहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं होता और वे अपने भविष्य की तलाश में दर-दर भटकने को मजबूर

हैं। जहां एक ओर प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है, वहीं देश के करोड़ों युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम करके सरकारी नौकरियों और पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तैयारी तो करते हैं, लेकिन बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा चोटाले उनकी मेहनत को हास्यस्पद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नीट

सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों ने युवाओं के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर बार-बार आवेदन शुल्क वसूलना, परीक्षाएं निरस्त करना, परिणामों में देरी और प्रशासनिक लापरवाही भी प्रतिभागियों के साथ बेमानी और अन्याय का प्रतीक बन चुकी है।

विडंबना यह है कि शिक्षा के लिए आवंटित सरकारी बजट का लाभ छात्रों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, जबकि दूसरी ओर युवा महंगी फीस, कोचिंग, आवेदन शुल्क और अन्य खर्चों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है और युवाओं की जेब पर अप्रत्यक्ष रूप से डाका डाला जा रहा है। शिक्षा और रोजगार पाने की प्रक्रिया इतनी महंगी होती जा रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवा अवसरों से वंचित हो रहे हैं।

इस पूरी व्यवस्था का सबसे खतरनाक प्रभाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वर्षों की मेहनत के बाद जब परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, परिणाम विवादों में फिर जाते हैं या भ्रष्टाचार के कारण योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं, तब युवाओं में निराशा, हताशा और अविश्वास पैदा होता है। अनेक युवा अवसाद का शिकार हो जाते हैं और कुछ आत्महत्या जैसा अप्रिय कदम उठाने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक विफलता है। बर्बाद होते युवाओं का भविष्य केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं है। इसका सीधा प्रभाव समाज और राष्ट्र

पर पड़ता है। जब योग्य युवाओं को अवसर नहीं मिलते, तब देश को युवा डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, नर्स और प्रशासक नहीं मिल पाते। बेरोजगारी, सामाजिक अस्तोष, अपराध, नशाखोरी और व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ता है। एक ऐसा समाज तैयार होता है जिसमें प्रतिभा हतोत्साहित और भ्रष्टाचार पुरस्कृत होता है।

सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि शिक्षा माफियाओं में कानून का भय लगभग समाप्त होता दिखाई दे रहा है। बार-बार चोटाले उजागर होने के बावजूद दोषियों पर कठोर कार्रवाई का अभाव उनके हौसलों को और बढ़ाता है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में व्याप्त यह अराजकता राष्ट्र के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। आज आवश्यकता केवल सुधारों की नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की है। शिक्षा को व्यापार और मुनाफे की मानसिकता से मुक्त कर राष्ट्र निर्माण का साधन बनाना होगा। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना होगा, शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करनी होगी तथा योग्य विद्यार्थियों को न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। यदि आज भी सरकारें, नीति निर्माता और जिम्मेदार संस्थाएं नहीं चेतीं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। क्योंकि जब शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पर हो और जिम्मेदार लोग तमाशाबाने बने रहें, तब केवल युवाओं का भविष्य नहीं, बल्कि पूरा राष्ट्र का भविष्य खतरे में पड़ जाता है।

देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए छात्रों की गूंज पूरे देश में गूंज रही है

ताजियों की जियारत करने उमड़ा जनसैलाब, या हुसैन' के नारों से गूंजा नगर

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

(राजेश नीरस) नगर में

मोहरम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया। संजय मार्केट के सामने मजमे में जायरीनों ने ताजियों की जियारत कर तबरक पेश किया। यौम-ए-आशुरा के दिन शहर के कोने-कोने से या हुसैन' के नारे बुलंदी के साथ सुनाई दिए। शहनाई की शहीदी धुन पर सवारियों बाबाओं की आमद के साथ पूरे शहर में रन करती हुई नजर आई



दोपहर तक संजय मार्केट के सामने ताजियों की जियारत करने के लिए जनसैलाब देखा गया। सुबह से ही नगर के सभी इमामबाड़ों से निकली सवारियां संजय मार्केट के सामने एकत्रित हुईं। जायरीनों ने अकीदत के साथ ताजियों पर इत्र-खुशबू और लोबान पेश किया। रेबड़ी का तबरक वकसीम किया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी ने ताजियों का दीदार कर मन्नत मांगी। सुबह से दोपहर तक मजमा लगा।

मजमे में बड़ी संख्या में मुरादियों ने बाबाओं से मुलाकात की। सवारियों के साथ चल रही बाबाओं की आमद के सामने मुरादियों ने प्याले नजर कर हाजरी लगाई और मन्नतें मांगीं। शहनाई की धुन पर सवारियों ने दरगाहों इमामबाड़ों में हाजरी पेश की। शहीदाने कर्बला की याद में सभी मस्जिदों में यौम-ए-आशुरा की

नमाज अदा की गई। जुमे की नमाज में भी भारी तदार उमड़े। जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, फैजाने में विवर्जित किए जाएंगे मोहरम

का माहौल पूरी तरह हुसैनी नजर आया। हर तरफ सिर्फ अकीदत और इंसायित का पैगाम सुनाई दे रहा था। संजय मार्केट के समक्ष जामा मस्जिद द्वारा बेहतर इंतजाम किए थे। नगर में लंगर का सिलसिला जारी है। शक्ति चौक पर हसनी हुसैनी सोसायटी द्वारा आम लंगर का विशाल रूप में आयोजन हुआ। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल खान ने मोहरम पर मिले प्रशासनिक सहयोग के प्रति आभार जताया।

मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने सुनीं लोगों की समस्याएं

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा

(राजेश नीरस) क्षेत्र की जनता

की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह ने शुक्रवार को सेवासन, लक्ष्मी टाउनशिप में जनसुनवाई की। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र से पधारे गणमान्य जन से सौजन्य मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।



मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जनता की समस्याएं हल करना हमारी प्राथमिकता है। पत्रा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय-सोमा में मिले। मंत्री ने सभी समस्याओं का निपटारा चरणबद्ध तरीके से करने का आश्वासन दिया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि संगठन की मजबूती ही सरकार की ताकत है। उन्होंने बृह स्तर तक सक्रिय रहने और जनता से निरंतर संपर्क में रहने की अपील की। उन्होंने आगे कहा

हमारी सरकार जनसेवा के लिए बनी है। हर कार्यकर्ता जनता का सेवक है। गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। यहां के हर नागरिक की समस्या मेरी समस्या है। हम मिलकर गाडरवारा को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष पंडित शिवाकांत मिश्रा, मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत शर्मा, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर योगेश कौरव, सभापति आनंद दुबे, भाजपा नेता अनूप जैन, राजेश जैन, सुरेश श्रीवास्तव सहित भाजपा के पदाधिकारी आम नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

जनहिताय सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकें भेंट की

साधना एक्सप्रेस गाडरवारा।

(राजेश नीरस) नगर के वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश बसेईडिया ने सार्वजनिक पुस्तकालय तितक भवन गाडरवारा को गत दिवस निर्जला एकादशी के अवसर पर साहित्य, पर्यावरण, योग, धर्म, व्यक्तित्व विकास, संत वाणी, तथा बाल सुलभ साहित्य के साथ अति दुर्लभ प्राचीन भाषा पहाड़े, आदि



से संबंधित 43 पुस्तकें प्रदान कीं। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक मधुसूदन पटेल एवं सार्वजनिक पुस्तकालय के ग्रंथपाल नेतराम कहार की उपस्थिति रही। इस मौके पर श्री बसेईडिया ने पुस्तकें प्रदान करते समय कहा कि पुस्तकालय को पुस्तक दान करने से ज्ञान का प्रसार होने के अलावा जरूरतमंद पाठकों को पढ़ने का अवसर मिलता है एवं पुस्तकों का सदुपयोग होता है जो कि यह सामाजिक और शैक्षिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है

आपातकाल लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात..जिला अध्यक्ष रामस्नेही पाठक

संविधान हत्या दिवस पर जिला कार्यालय में हुआ लोकतंत्र सेनानियों का किया सम्मान



साधना एक्सप्रेस नरसिंहपुर

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर 'आपातकाल का काला अध्याय' विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके

परिजनों का शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मान किया गया कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर आघात पहुंचाया था। लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष और त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके योगदान से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती

मिली और आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र की रक्षा का संदेश मिला लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी संघ के संरक्षक रमेश कोचर, जिलाध्यक्ष मुन्नालाल नामदेव, संतोष तिवहिया, विजय सोनी लेखचंद कोचर, हीरेन्द्र चौधरी, अरविंद गुप्ता तथा लालजी रैकवार का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष रामस्नेही पाठक,

डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हुए कार्यक्रमों का प्रशिक्षण - भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत बृह स्तरीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सोशल मीडिया जिला संयोजक श्रीकांत श्रीवास्तव ने डिजिटल माध्यमों के प्रभावी उपयोग, संगठनात्मक गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा सोशल मीडिया की भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी।

बड़नगर की घटना पर गजरे शिवसेना के अनुराग सोनार: मोहरम जुलूस में खतरनाक प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, प्रशासन दे जवाब

साधना एक्सप्रेस उज्जैन।

उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहरम जुलूस के दौरान कथित रूप से क्रेन से एक वाहन को लटककर उसमें विस्फोटक/पटाखों का प्रदर्शन किए जाने की घटना पर शिवसेना युवासेना मध्यप्रदेश के राज्य प्रमुख अनुराग सोनार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।



अनुराग सोनार ने कहा कि 'धार्मिक आयोजनों की आड़ में कानून-व्यवस्था को चुनौती देना और आम जनता की जान जोखिम में डालना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके विरुद्ध बिना किसी भेदभाव

एक घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिह्न है। यदि सावजनिक स्थान पर इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ, तो इसकी अनुमति नहीं दी, सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या थी-इसकी उच्च

स्तरीय जांच कर जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

अनुराग सोनार ने कहा कि 'शिवसेना युवासेना मध्यप्रदेश कानून से ऊपर किसी को नहीं मानती। यदि दोषियों पर शौधर और कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में व्यापक जनआंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

उन्होंने प्रदेशवासियों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और कानून का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।